RNI NO. CHHHIN/2022/83778

E-mail: newsroutine6@gmail.com

न्यूज रूटीन

www.newsrourine.in

बढ़ते हुए कदम

वर्ष- 05 अंक -04 अप्रैल 2026 मूल्य - 35 रु.

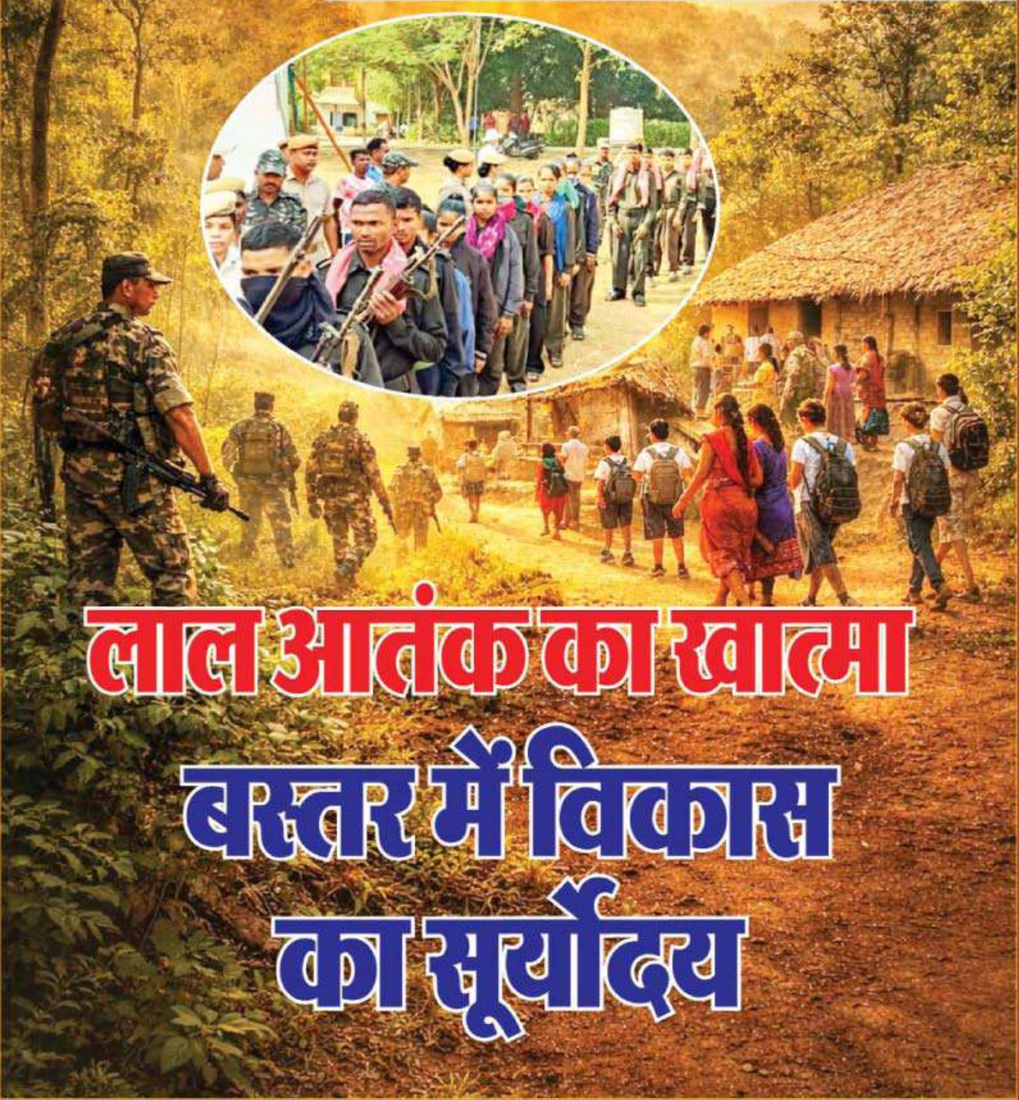

लाल आतंक का खात्मा

बस्तर में विकास का सूर्योदय

165 करोड़ से संवरेगी हसदेव की धारा

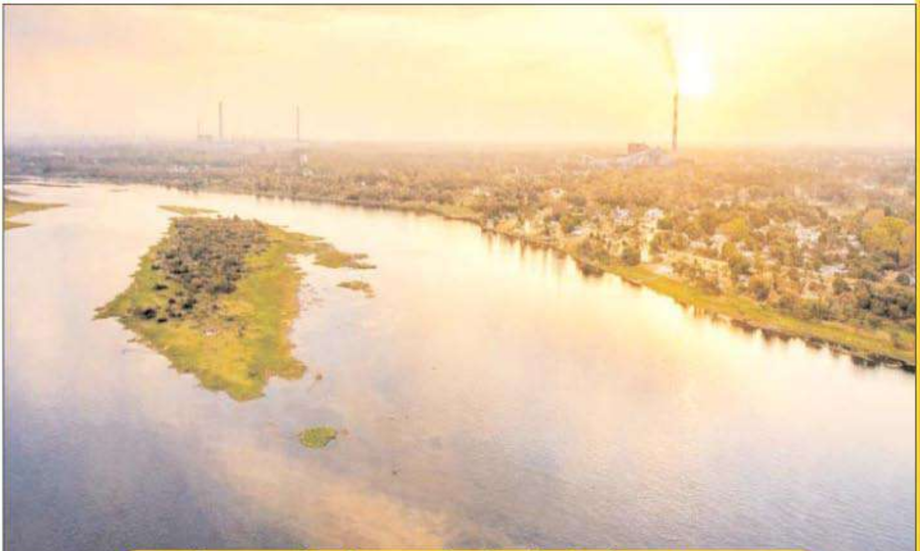

कोरबा की जीवनदायिनी को मिलेगा 'अमृत'

अमृत मिशन 2.0 के तहत 20 एमएलडी क्षमता के टर्शरी ट्रीटमेंट प्लांट को मिली मंजूरी, प्रदूषण-मुक्त होगी

ऊर्जाधानी कोरबा की जीवनरेखा मानी जाने वाली हसदेव नदी अब प्रदूषण के काले साये से मुक्त होकर फिर से कल-कल बहेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की महत्वाकांक्षी 'अमृत मिशन 2.0' योजना ने कोरबा में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि जोड़ दी है। छत्तीसगढ़ शासन के प्रयासों से भारत सरकार ने शहर के दूषित जल के वैज्ञानिक उपचार हेतु 165 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है।

सालों से शहर के 11 बड़े नालों का दूषित सीवरेज जल सीधे हसदेव नदी में मिलकर उसकी शुद्धता को प्रभावित कर रहा था। इस गंभीर समस्या के स्थायी समाधान के लिए 20 एमएलडी क्षमता का अत्याधुनिक टर्शरी ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया जा रहा है।

प्रतिदिन लगभग 3 करोड़ 30 लाख लीटर दूषित जल को नदी में गिरने से पहले ही रोककर अत्याधुनिक तकनीक से उपचारित किया जाएगा। इससे नदी के प्रदूषण में भारी कमी आएगी और उसका जल पुन: स्वच्छ बनेगा। परियोजना के पूर्ण होते ही कोरबा उन चुनिंदा 12 शहरों की सूची में शामिल हो जाएगा, जहाँ जल शोधन की ऐसी उन्नत और वैज्ञानिक व्यवस्था उपलब्ध है।

यह परियोजना केवल नदी की सफाई तक सीमित नहीं है, बल्कि 'वेस्ट टू वेल्थ' का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी बनेगी। उपचारित किए गए करोड़ों लीटर पानी को बर्बाद करने के बजाय एनटीपीसी द्वारा निर्धारित दरों पर खरीदा जाएगा। इससे उद्योगों को स्वच्छ जल उपलब्ध होगा, नगर निगम के राजस्व में वृद्धि होगी और भू-जल संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत ने इसे कोरबा जिले के लिए ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के मानकों का पालन करते हुए नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा तैयार किए गए इस वैज्ञानिक समाधान को अब वास्तविक रूप मिलने जा रहा है। वर्तमान में निविदा प्रक्रिया प्रगति पर है और जल्द ही निर्माण कार्य धरातल पर शुरू हो जाएगा। अमृत मिशन 2.0 के तहत यह प्लांट न केवल हसदेव नदी को पुनर्जीवित करेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जल संरक्षण की नई मिसाल भी पेश करेगा। इसके माध्यम से कोरबा औद्योगिक प्रगति के साथ-साथ पर्यावरणीय स्वच्छता के क्षेत्र में भी अग्रणी बनेगा।

कोरबा की जीवन रेखा कहलाती है हसदेव नदी

कोरबा की जीवनदायिनी नदी हसदेव नदी का उद्गम स्थल कोरिया जिले में है, जहां से बहकर लगभग 125 किलोमीटर बाद नदी कोरबा में प्रवेश करती है. सैकड़ों एकड़ खेतों की सिंचाई भी हसदेव के ही जल पर निर्भर होती है. कोरबा नगर निगम हसदेव के पानी को ट्रीटमेंट के बाद लोगों के घरों तक पहुंचाता है. जिससे लाखों लोगों की प्यास बुझाती है. यही कारण है कि हसदेव न सिर्फ मनोरम है, बल्कि वह जीवनदायिनी भी है. जीवनदायिनी हसदेव नदी इस साल जरूर मुस्कुरा रही है, लेकिन बीते लगभग एक दशक से भी ज्यादा समय से हसदेव भीषण प्रदूषण की चपेट में है. इसे बचाने के लिए पर्यावरणविदों ने हसदेव बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी. हसदेव नदी बुरी तरह से औद्योगिक प्रदूषण की मार झेल रही है. हाल ही में पर्यावरण संरक्षण मंडल कोरबा की टीम ने कुसमुंडा कोयला खदान को नोटिस जारी कर हसदेव में प्रदूषित पानी नहीं बहाने की हिदायत दी थी.

न्यूज रूटीन

बढ़ते हुए कदम

● वर्ष: 05 ● अंक:04 ● अप्रैल 2026

RNI NO. CHHHIN/2022/83778

E-mail: newsroutine6@gmail.com

सारंगढ़-बिलाईगढ़

प्रधान संपादक

गुलाब दास दीवान

सहसंपादक

प्रवीण खरे

कानूनी सलाहकार

जवाहर पड़वार

इंदुभूषण पड़वार

प्रधान कार्यालय

न्यूज़ रूटीन

बाजार काम्पलेक्स, नगर पंचायत पवनी,
जिला- सारंगढ़ बिलाईगढ़
पिन. नं. 493338
मो.नं. 9294743139

रायपुर कार्यालय

फ्लैट नं. 109, सी ब्लाक, कमल हाईट्स,
सेक्टर-4, कमल विहार, रायपुर (छ.ग.)
पिन नं. 492004
मो. नं. 6261155546

न्यूज रूटीन में प्रकाशित आलेखों से संपादक, प्रकाशक, मुद्रक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है। विवादग्रस्त न्यायिक प्रकरणों का कार्यक्षेत्र सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला रहेगा। सभी पद पूर्णतः मानसेवी व अवैतनिक। समाचार स्त्रोत हमारे सभी संवाददाता/प्रतिनिधि। संदर्भ सामग्रीः इंटरनेट, प्रमुख समाचार पत्र एवं नामचीन पत्रिकाओं से सादर साभार।

संपादक- गुलाब दास दीवान

अंदर के पृष्ठों में

7 नक्सल मुक्त भारत के बाद 'ऑपरेशन द एंड' शुरू

16 आधुनिक तकनीक के साथ संवेदनशीलता ही नई पुलिसिंग की पहचान

- देश हुआ नक्सल मुक्त 5
- अब बस्तर का विकास प्राथमिकता 8
- होर्मुज की लहरों में डूबता सुपर पावर का गुमान 10
- नेपाल की नयी सरकार से उम्मीदें बहुत 12
- जल संरक्षण का कोरिया मॉडल बना राष्ट्रीय उदाहरण 13
- एक साल में 6 लाख आवासों का काम पूरा 19
- शहर में 15 और गांव में 30 मिनट में पहुंचेगी 108 सेवा 20
- आईएएस रजत बंसल बने जनसंपर्क आयुक्त, सीएम... 23
- नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बंद पड़े 123 स्कूल फिर से गुलज़ार 25
- एशियन गेम्स का पदक जीतना मेरा अधूरा सपना 26
- अपने भीतर के हनुमान को जगाने का पर्व 29

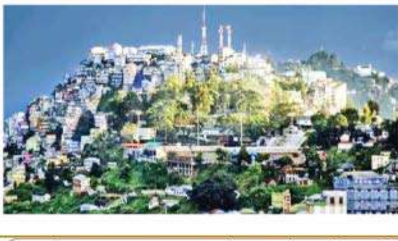

बादलों के बीच बसा आइजोल 30

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक- गुलाब दास दीवान, द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि. (छ.ग.) भवन, प्रेस काम्पलेक्स रजबंधा मैदान रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित एवं ग्राम-पोस्ट-पवनी, तहसील-बिलाईगढ़, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.), 493338 से प्रकाशित। RNI NO. CHHHIN/2022/83778 सम्पादक- गुलाब दास दीवान, मो. 9294743139

नक्सल-मुक्त भारत का पूरा हुआ सपना

गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार, 30 मार्च को संसद के जरिये देश को सूचित किया कि बस्तर से नक्सलवाद खत्म हुआ। उन्होंने देश से नक्सलवाद के खात्मे की समय-सीमा 31 मार्च, 2026 तय की थी। गौर कीजिए, करीब 17 साल पहले (साल 2009 में) तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नक्सलवाद को देश की 'आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा और गंभीर खतरा' बताया था, मगर आज हम यह कहने की स्थिति में हैं कि यह अब हमारे लिए चुनौती नहीं रहा।

ऐसे किसी भी आंदोलन के अंत के दो मानक होते हैं- पहला, संगठन का एक भी कार्यकर्ता न बचे और दूसरा, उसका कार्य-क्षेत्र पूरी तरह से सिमट जाए। एक भी नक्सली नहीं बचा, ऐसा दावा करना तो उचित भी नहीं, है, पर सच यह भी है कि जब नक्सलवाद अपने चरम था, तब इसके चार से पांच हजार काडर थे। आज इनकी संख्या बमुश्किल 100 से 150 होगी। वे भी ऐसे नक्सली होंगे, जिनकी सांगठनिक अहमियत शायद ही हो।

हां, दूसरा मानक अधिक महत्वपूर्ण है। नक्सलवाद का गढ़ बस्तर रहा है। इसे केंद्र में रखकर यदि वृत्ताकार नक्शा बनाएं, तो ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड जैसे तमाम राज्यों के इलाके इसकी जद में थे। नेपाल में भी वामपंथी आंदोलन सक्रिय था, जिसके कारण 'पशुपति से तिरुपति तक लाल गलियारा बनाने का' नारा खूब गूंजा करता था। अब इस गलियारे का कोई नामलेवा नहीं। नेपाल में तो नक्सलियों ने अपनी राजनीतिक पार्टी बना ली थी, हालांकि इस बार के चुनाव में नेपाल की जनता ने भी उनको पूरी तरह नकार दिया है। फिर, दंडकारण्य में हमारे सुरक्षा बलों की व्यापक पहुंच हो गई। नतीजतन, नक्सलियों का ढांचा ढहने लगा।

वास्तव में, नक्सलवाद के खिलाफ जो रणनीति बनाई गई, उसमें कई खास बातें थीं। पहली, जंगल के अंदरूनी इलाकों में सुरक्षा बलों के कैंप लगाए गए। आज सीआरपीएफ, बीएसएफ या स्थानीय डीजी गार्ड्स के शिविर घने जंगलों में भी देखे जा सकते हैं। यह रणनीति कमोबेश 2010 के दंतेवाड़ा नक्सली हमले के बाद ही बनाई गई, जिसमें नक्सलियों ने 75 से अधिक सीआरपीएफ जवानों की जान ले ली थी। यह घटना नक्सलवाद के खात्मे की प्रतिबद्धता के लिहाज से 'टर्निंग प्वॉइंट' साबित हुई। चूंकि इस हादसे के बाद सुरक्षा बलों के कैंप जहां-तहां लगने लगे, इसलिए नए रंगरूटों की भर्ती में नक्सलियों को दिक्कतें होने लगीं।

इस दरम्यान, संगठन के मुख्य नेतृत्व को या तो मार गिराया गया या उसने अपने हथियार डाल दिए। पापाराव संभवत: आखिरी नेतृत्व है, जिसने अभी-अभी आत्म-समर्पण किया है। इस तरह नक्सलवाद आंदोलन में अब दम नहीं बचा है। कुछ नक्सली जरूर जंगल में होंगे, पर मुमकिन है कि उनको इस आत्मसमर्पण की खबर नहीं हो, क्योंकि वहां संचार के साधन अब भी कमजोर हैं। ऐसे में, बाद के दिनों में या तो वे भी अपने हथियार डाल देंगे या चुपचाप मुख्यधारा में लौट आएंगे, ठीक उन खालिस्तानियों की तरह, जिन्होंने पंजाब में सैन्य कार्रवाई के बाद अपने हथियार नदियों या कुओं में फेंककर या जमीनों में गाड़कर चुपचाप सामान्य जीवन जीना शुरू कर दिया। ऐसे लोग यदि कोई उपद्रव नहीं करते, तो पुलिस इन पर हाथ नहीं डालती।

नक्सलवाद-विरोधी रणनीति की एक खासियत सरकारों द्वारा सड़क व बुनियादी ढांचे की बेहतरी पर काम करना भी है। अब तो जंगली इलाकों में भी मोबाइल फोन के टावर दिखने लगे हैं, जिस कारण सुरक्षा बलों के बीच संचार बढ़ा है और वे अपनी कार्रवाइयां कहीं अधिक सटीक तरीके से अंजाम देने लगे हैं। जवानों को अत्याधुनिक तकनीकों से लैस करना भी कारगर रहा। 'नाइट विजन डिवाइस' के साथ-साथ अब वे ड्रोन का इस्तेमाल करने लगे हैं। ड्रोन का फायदा यह हुआ कि पहाड़ी इलाकों में दूसरी तरफ की गतिविधियों की जानकारी भी सशस्त्र बलों के पास पहुंचने लगी। उन्हें नए-नए हथियार दिए गए हैं।

सबसे बड़ी बात यह हुई कि छत्तीसगढ़ पुलिस का रूप-रंग बदला गया। मुझे याद है, पहले उसके पास न तो संख्या बल था, न खास प्रशिक्षण और न ही पर्याप्त संसाधन। जब यह राज्य मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, तब बमुश्किल कुछ सैकड़ा सिपाही रहे होंगे। रात में थाने बंद कर दिए जाते थे। मगर बाद के वर्षों में इनकी संख्या बढ़ी और अब तो 70-80 हजार सिपाही वहां कार्यरत हैं। इससे बड़ा फर्क आया। दरअसल, राज्य पुलिस स्थानीय चुनौतियों से बखूबी परिचित होती है। मसलन, नक्सली स्थानीय भाषा गोंडी का इस्तेमाल करते हैं, जिनको समझ पाना केंद्रीय सशस्त्र बलों के लिए कठिन होता है। राज्य पुलिस इसमें दक्ष होती है। उसका सूचना तंत्र भी बेहतर होता है। जाहिर है, जब राज्य पुलिस संसाधनों से संपन्न हो गई और उनकी संख्या बढ़ गई, तो इसका असर जमीन पर होना ही था। लिहाजा, नक्सल-मुक्त भारत का सपना यदि आज साकार हो रहा है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण किरदार राज्य पुलिस ने ही निभाया है।

संपादक

सम्पादकीय

नक्सलवाद-विरोधी रणनीति की एक खासियत सरकारों द्वारा सड़क व बुनियादी ढांचे की बेहतरी पर काम करना भी है। अब तो जंगली इलाकों में भी मोबाइल फोन के टावर दिखने लगे हैं, जिस कारण सुरक्षा बलों के बीच संचार बढ़ा है और वे अपनी कार्रवाइयां कहीं अधिक सटीक तरीके से अंजाम देने लगे हैं।

देश हुआ नक्सल मुक्त

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश को नक्सल मुक्त करने की 31 मार्च रखी गई डेडलाइन से एक दिन पहले 30 मार्च को ही लोकसभा में देश नक्सल मुक्त होने की घोषणा कर दी

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश को नक्सल मुक्त करने की 31 मार्च रखी गई डेडलाइन से एक दिन पहले 30 मार्च को ही लोकसभा में देश नक्सल मुक्त होने की घोषणा कर दी। इसके आधार में उनका कहना है कि 2024 तक नक्सलियों की टॉप सेंट्रल कमिटी और पोलित ब्यूरो में 21 मुख्य कैडर थे।

मारे गए 12 टॉप नक्सली

जो नक्सलियों के इस पूरे नेटवर्क को चलाते थे। ताजा स्थिति की बात करें तो इनमें से एक पकड़ा गया, सात ने आत्मसमर्पण कर दिया और 12 टॉप कैडर मारे गए। केवल एक नक्सली ही फरार है और उसके साथ भी बातचीत चल रही है। इस एक फरार नक्सली के बारे में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह मिशिर बेसरा है। जो झारखंड के सारंडा जंगलों में अपने करीब 50 साथियों के साथ छिपा हुआ है।

देश में खत्म हो जाएंगे लिस्टिड नक्सली

इसका अपने कैडर के साथ सरेंडर कराने की कोशिश की जा रही है। अगर इसने वार्ता का जवाब वार्ता से दिया तो ठीक है, वरना गोली का जवाब गोली से ही दिया जाएगा। इसके आत्मसमर्पण करने के साथ ही देश में हथियारों के बल हिंसा करने वाले लिस्टिड नक्सली खत्म हो जाएंगे। रही बात 80 साल के बूढ़े गणपति की तो उसके लोकेशन के बारे में कोई इनपुट नहीं है। मौजूदा समय में अब हथियार उठाकर हिंसा करने वाला कोई नक्सली नहीं बचा है।

जांच में लगा पता

1970 के दशक में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से शुरू हुआ माओवाद 12 राज्यों तक फैल गया। यह तिरूपति से पशुपति नाथ तक रेड कॉरिडोर के रूप में फैल गया था। इसके बनने के एक साल बाद 1971 में ही हिंसा की 3620 घटनाएं दर्ज की गईं। नक्सलियों के पास जितने भी हथियार बरामद हुए। बाद में उनकी जांच में पता लगा कि इनमें से 92 फीसदी हथियार पुलिस बलों और थानों से लूटे हुए थे।

कांग्रेस शासन के बाद भी क्यों नहीं हुआ विकास

नक्सली इलाकों में विकास ना होने के कांग्रेस सदस्यों के आरोपों पर भी अमित शाह ने कहा कि 75 सालों में 60 साल तक तो शासन कांग्रेस ने ही किया तो आदिवासी विकास के बिना क्यों रह गए। अपने गिरेंबा में छांककर देखेंगे तो पता लग जाएगा कि दोषी कौन है। छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा समेत 12 राज्यों में रेड कॉरिडोर था। वहां कानून का शासन समाप्त हो चुका था। करीब 20 हजार लोग मारे गए।

मनमोहन सिंह ने भी कही थी ये बात

लोगों ने नर्क का जीवन जिया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी अपने कार्यकाल में कहा था कि कश्मीर और नॉर्थ-ईस्ट की तुलना में देश की आंतरिक सुरक्षा की सबसे बड़ी चिंता माओवादी हैं। गृह मंत्री ने नक्सल मुक्त करने के लिए सीएपीएफ के जवानों विशेषकर कोबरा, सीआरपीएफ, राज्यों की पुलिस में विशेषकर छत्तीसगढ़ पुलिस, डीआरजी जवान और स्थानीय आदिवासियों को इसका श्रेय दिया।

स्टेट की पहुंच कम होने के कारण रेड कॉरिडोर चुना

नक्सलियों ने बस्तर समेत जो भी इलाके अपने लिए चुने। वह अत्याचार से मुक्त होने के लिए नहीं बल्कि अपनी पेरलल सरकार चलाने के लिए। इस पूरे रेड कॉरिडोर को इसलिए चुना

था कि वहां स्टेट की पहुंच कम थी। भोले-भाले आदिवासियों को बरगलाकर, उनके हाथों में हथियार पकड़ा दिए गए।

अपना आधार खो बैठी वामपंथी विचारधारा

गृह मंत्री शाह ने साफ लफ्जों में कहा कि माओवादी हिंसा करने वालों का दिन लद गया है। वामपंथी विचारधारा अपना आधार खो बैठी है। इनका एक मात्र एजेंडा है देश में वैक्यूम खड़ा करना। नक्सलियों ने भोले गांव वालों को दुश्मन का मुखबिर बताकर फांसी पर चढ़ा दिया। वह स्वयं फैसला करते थे, फांसी देते थे। इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता।

संविधान के तहत होगा फैसला हथियारों से नहीं

देश में संविधान के तहत ही फैसला होगा, हथियारों से नहीं। नक्सलियों ने पेरलल सरकार चलाई। छत्तीसगढ़ के बस्तर में उनका होम मिनिस्टर और न्याय मंत्री होता था। लूटे गए अनाज को बांटने वाला खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री होता था। इन्होंने विकास की योजनाओं को रोकने का काम किया। मतदान नहीं होने दिए।

मैं पहले ही दे चुका उनको चेतावनी

बाकी बचे नक्सलियों के लिए गृह मंत्री ने कहा कि मैं 50 बार कह चुका हूं। हथियार डाल दीजिए, सरकार आपके पुनर्वास की व्यवस्था करेगी। अगर हथियार नहीं डाले तो जो गोली चलाएगा उसका जवाब गोली से ही दिया जाएगा। यह हमारी सरकार की पॉलिसी है। वोट की जगह बुलेट से यह लोग शासन चलाना चाहते थे। यह बीजेपी की सरकार है।

क्या कहते हैं 2024 से अब तक के आंकड़ें

हर नागरिक की सुरक्षा मोदी सरकार ने सुनिश्चित की है। जो समझा ठीक, वरना यह फोर्स इसी के लिए बनाई गई है। उन्होंने नक्सलियों से पीड़ित आदिवासी और गांव वालों की वेदना पर भी बात की और कहा कि क्या विपक्ष ने कभी इन लोगों के दुख दर्द को देखा है। जरा कैंपों में जाकर तो देखो, फिर पता लगेगा कि नक्सलियों ने कितनों के घर उजाड़े। नक्सलियों को मुठभेड़ में मारे जाने के मामले में भी शाह ने कहा कि 2024 से अब तक केवल 706 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए हैं। जबकि 2218 को गिरफ्तार किया गया और 4849 ने सरेंडर किया।

पहले बिरसा मुंडा को मानते थे नायक ...

उन्होंने कहा कि गरीबी के कारण नक्सलवाद नहीं फैला, बल्कि नक्सलवाद के कारण सालों तक गरीबी रही। शाह ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि 15 अगस्त 1947 से पहले आदिवासी बिरसा मुंडा, तिलका मांझी को नायक मानते थे। वे 70 का दशक आते-आते माओ को नायक कैसे मानने लगे।

नक्सल मुक्त भारत के बाद अब क्या होगी आगे की रणनीति

देश से नक्सलवाद के खात्मे का आधिकारिक ऐलान हो चुका है। गृहमंत्री अमित शाह ने खुद संसद से इसकी घोषणा की है। ऐसे में अब सवाल यह उठ रहा है कि डेडलाइन (31 मार्च) खत्म होने के बाद अब नक्सल प्रभावित इलाकों का भविष्य क्या होगा। अगर आगे कोई शख्स नक्सल से प्रभावित होकर लाल आतंक के रास्ते पर चला जाता है तो उससे सरकार किस तरह से निपटेगी। क्या बंदूक का जवाब बंदूक से दिया जाएगा या फिर सरकार ने इसके लिए कोई और योजना सोच रखी है। आइए आपको बताते हैं।

सरेंडर के साथ साथ पुनर्वास पर जोर

सरकार एक तरफ नक्सलियों के सरेंडर पर जोर दे रही है तो वहीं दूसरी तरफ सरेंडर कराने के बाद उनके पुनर्वास पर भी फोकस कर रही है। इसके लिए पहले से ही 'पूना मारगेम' या नई सुबह जैसी नीति चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को मुख्यधारा में लौटाना है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास पर ध्यान

सरकार नक्सल से प्रभावित इलाकों के विकास पर अब ज्यादा ध्यान दे रही है। नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस कैंप के आसपास स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ शिक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है। ताकी पढ़-लिखकर आदिवासी युवा नक्सलवाद की हकीकत को समझ पाएं। इसके अलावा सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को ठीक करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

जागरूकता फैलाने पर कर रहे फोकस

गृह मंत्री अमित शाह देश से नक्सलवाद खत्म होने का ऐलान कल (30 मार्च) संसद में कर चुके हैं। ऐसे में अब सरकार का पूरा फोकस है कि किसी भी तरह से दोबारा नक्सलवाद फैलना शुरू न हो। इसके लिए एक वर्क प्लान बनाया गया है, जिसके तहत नक्सल प्रभावित इलाके के लोगों खासतौर पर युवाओं को शिक्षा के साथ-साथ रोजगार से भी जोड़ा जाएगा। ताकी वे आतंक के रास्ते पर ध्यान न देकर मुख्यधारा से जुड़ें।

बंदूक की लड़ाई से हटा सरकार का फोकस?

कुल मिलाकर सरकार का फोकस अब गन फाइट (बंदूक की लड़ाई) से हटकर आत्मसमर्पण और नक्सलियों को मुख्यधारा में लाने का है। इसके लिए नक्सलवादियों के सरेंडर पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है और उम्मीद यही की जा रही है कि आगे भी सरकार इस नीति पर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित कर सकती है।

बदल रही बस्तर की पहचान

बस्तर, जो कभी नक्सल हिंसा का केंद्र माना जाता था, अब तेजी से बदलते भारत की नई पहचान बनकर उभर रहा है. केंद्र और राज्य सरकार ने पहले ही विकास की जो नींव रखी थी, अब उसे और मजबूत करने के लिए व्यापक खाका तैयार किया गया है. नई औद्योगिक नीति में बस्तर को विशेष प्राथमिकता दी गई है, जहां स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है. इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी.

युवाओं को इस बदलाव का केंद्र बनाया गया है. कौशल विकास योजनाओं के माध्यम से उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित कर रोजगार से जोड़ा जा रहा है. यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि बस्तर का युवा अब बंदूक नहीं, बल्कि अपने कौशल और मेहनत से अपनी पहचान बनाए।

नक्सल मुक्त भारत के बाद 'ऑपरेशन द एंड' शुरू

नक्सलियों के अर्थतंत्र और स्मारकों पर बुलडोजर एक्शन

नक्सल मुक्त भारत का ऐलान हो चुका है, अब केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसी और सुरक्षाबल मिलकर नक्सलियों के आर्थिक तंत्र को पूरी तरीके से खत्म करने के साथ-साथ नक्सलियों की विचारधारा को समाप्त करने का अभियान तेजी से शुरू किया है, नक्सलियों की अर्थ तंत्र को खत्म करने के लिए सुरक्षा बलों ने एक बड़ा अभियान अबूझमाड़ के जंगलों में शुरू किया है, इसी इलाके में नक्सलियों में अपने जो स्मारक बना रखे थे. उनको भी तोड़ा जा रहा है, पिछले एक महीने की अगर बात करें तो सुरक्षा बलों ने बस्तर के इलाके में 12 करोड़ से ज्यादा मूल्य के रुपये और सोना बरामद किए हैं, जिसमें 6 करोड़ 75 लाख रुपये नगद और 8 किलोग्राम सोना नक्सलियों के डंप से बरामद किया गया है.

केंद्र और राज्य सरकारों ने 'नक्सल मुक्त भारत' के ऐलान के बाद अब नक्सलियों की जड़ों को काटने के लिए 'ऑपरेशन द एंड' छेड़ दिया है. पिछले एक महीने में सुरक्षाबलों ने नक्सलियों के गुप्त ठिकानों से 12 करोड़ की संपत्ति और 300 से ज्यादा स्मारक ध्वस्त कर उनकी विचारधारा पर कड़ा प्रहार किया है.

नक्सल मुक्त भारत का ऐलान हो चुका है, अब केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसी और सुरक्षाबल मिलकर नक्सलियों के आर्थिक तंत्र को पूरी तरीके से खत्म करने के साथ-साथ नक्सलियों की विचारधारा को समाप्त करने का अभियान तेजी से शुरू किया है, नक्सलियों की अर्थ तंत्र को खत्म करने के लिए सुरक्षा बलों ने एक बड़ा अभियान अबूझमाड़ के जंगलों में शुरू किया है, इसी इलाके में नक्सलियों में अपने जो स्मारक बना रखे थे. उनको भी तोड़ा जा रहा है, पिछले एक महीने की अगर बात करें तो सुरक्षा बलों ने बस्तर के इलाके में 12 करोड़ से ज्यादा मूल्य के रुपये और सोना बरामद किए हैं, जिसमें 6 करोड़ 75 लाख रुपये नगद और 8 किलोग्राम सोना नक्सलियों के डंप से बरामद किया गया है. यहां पर नक्सलियों ने ये रुपये नक्सलवाद फैलाने के लिए जमा कर रखे थे. अब जब की देश के विभिन्न इलाकों से नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म हो गया है ऐसे में सुरक्षा बल नक्सलियों के गढ़ में जाकर के उनके हथियारों के डंप रूपए- पैसे सोना चांदी यह तमाम चीज ढूंढने में जुटी हुई है, खास तौर पर उन इलाकों में जहां पर नक्सलियों ने अपनी सुरक्षित राजधानी बना रखी थी.

जानकारी मिली है कि नक्सलियों के करीब 300 से ज्यादा स्मारकों को सुरक्षा बलों ने पिछले एक से दो महीने के अंदर नष्ट किया है, स्मारकों को नष्ट करने के पीछे का मकसद ये है कि नक्सली विचारधारा को पूरी तरीके से अबूझमाड़ के जंगलों से खत्म कर देना है.

यही वजह है इन तमाम इलाकों में बुलडोजर के जरिए अभियान सुरक्षा बलों के द्वारा चलाए जा रहा है. DRG/STF/CoBRA/बस्तर फाइटर्स/CRPF/BSF/ITBP/SSB/CAPF ने स्थानीय प्रशासन तथा अन्य सभी हितधारकों के साथ समन्वित प्रयास करते हुए असंभव को संभव कर दिखाया है.

बस्तर संभाग में एक महीने में 170 माओवादी कैडरों की मुख्यधारा में वापसी- विभिन्न जिलों में बड़ी संख्या में कैडरों ने हिंसा का मार्ग त्यागकर समाज के साथ जुड़ने का निर्णय लिया. पिछले एक महीने में 343 से अधिक घातक हथियार बरामद- AK-47, INSAS, SLR, BGL लांचर और LMG जैसे हथियारों की बड़ी बरामदगी ने माओवादी सैन्य क्षमता को लगभग समाप्त कर दिया है.

12 करोड़ से अधिक नकदी की बरामद

पिछले एक महीने में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के डंप से भारी आर्थिक संसाधन बरामद किए है- पिछले 31 दिनों में रू. 6.75 करोड़ नकद तथा 8 किलोग्राम सोना (रू.12 करोड़ से अधिक मूल्य) की बरामदगी माओवादी

तंत्र के आर्थिक आधार के कमजोर होने का स्पष्ट संकेत है. डंप रिकवरी में ऐतिहासिक उपलब्धि- नक्सल विरोधी अभियानों के इतिहास में एक ही महीने की अवधि में इतनी बड़ी नकदी और सोने की बरामदगी एक महत्वपूर्ण कीर्तिमान है.

उधर, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने नक्सल-विरोधी अभियान में नक्सली अर्थ तंत्र को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए एक समर्पित विभाग की स्थापना की है, जिसने 108 मामलों की जांच की और 87 मामलों में आरोपपत्र दाखिल किए, जिससे त्वरित अभियोजन के ज़रिए नक्सलवादी संगठनात्मक संरचना को काफी कमजोर कर दिया गया, इसके साथी शहरों में रह रहे नक्सलियों के मददगारों के अर्थतंत्र को भी पूरी तरीके से एनआईए ने ध्वस्त किया है.

300 से ज्यादा स्मारकों पर एक्शन

ग्राउंड पर जाकर के हमने तमाम लोकेशन पर देखा है कि अबूझमाड़ के जंगलों में नक्सलियों ने जो अपने नक्सली विचारधारा को पनपनाने के लिए नक्सली ट्रेनिंग सेंटर के पास बड़े-बड़े वैचारिक स्मारक बना रखे थे. इन स्मारकों को सुरक्षा बलों ने बुलडोजर के जरिए ध्वस्त कर दिया है. इन पर बुलडोजर प्रहार ये दिखाता है कि नक्सलियों के दिल और उनके दिमाग पर उनकी विचारधारा को पूरी तरीके से ध्वस्त सरकार के द्वारा किया जा रहा है.

अब तक की जानकारी के मुताबिक ऑपरेशन के जरिए नक्सलियों के 300 से ज्यादा विचारधारा को पुष्पित और प्रज्वलित करने वाले स्मारकों को अबूझमाड़ की घने जंगलों में ध्वस्त किया गया है. देशभर में नक्सलियों की स्मारकों को ध्वस्त करने का एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है. ग्राउंड से जो हमें आंकड़े मिले हैं. उसके मुताबिक, जिसके तहत महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में दोनों राज्यों में मिलाकर अब तक 300 से ज्यादा नक्सली मॉन्यूमेंट्स ध्वस्त किए गए हैं. सबसे ज्यादा कार्रवाई वर्ष 2026 में हुई है, जिसमें छत्तीसगढ़ में 200 और महाराष्ट्र में 100 से ज्यादा नक्सली स्मारकों (मॉन्यूमेंट्स) तोड़े गए.

हथियार, उनके डंप तथा IED भारी मात्रा में पकड़े गए... नक्सली इलाके के रिपोर्टिंग के दौरान हमने देखा कि किस तरीके से नक्सलियों ने अलग-अलग पहाड़ी इलाकों की गुफाओं में भारी मात्रा में आईईडी रॉकेट लांचर बनाने की फैक्ट्रियां बंदूक बनाने के लिए देसी स्टाइल मशीन की लगा रखी थी, जिनको की अब लगातार सुरक्षा बल नष्ट कर रहे हैं. आंकड़ों की अगर बात करें तो वर्ष 2024 से 2026 की अवधि के दौरान नक्सलवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए नक्सलियों के डंप ढूंढने के अभियानों में बड़ी सफलता हासिल हुई है.

इस दौरान नक्सलियों के कब्जे से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं. वर्ष 2024-26 की अवधि में नक्सलियों के कब्जे से AK-47, SLR, INSAS, .303 राइफल और BGL लॉन्चर सहित कुल 1031 हथियार बरामद किए गए.

दूसरी ओर इस अवधि में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों का एक भी हथियार लूटने में सफल नहीं हो सके जो सुरक्षा बलों की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. नक्सलियों द्वारा जंगल और पहाड़ी इलाकों में लगाए गए इृश्वष्ठ (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) को खोजने और निष्क्रिय करने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है.

इस विशेष अभियान के तहत वर्ष 2025 में सबसे अधिक 894 IED बरामद और निष्क्रिय किए गए.

निष्कर्षइन अभियानों से साफ है कि सुरक्षा बलों का नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार सफल रहा है, हथियारों की बरामदगी बढ़ी है और IED निष्क्रिय करने में भी बड़ी सफलता मिली है, जबकि नक्सलियों सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने में काफी हद तक नाकाम रहे हैं.

20 अलग-अलग टीमें तैनात

गृह मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार कि नक्सली इलाके में नक्सलियों के विस्फोटकों, जिनको की गुफाओं में छुपा रखा है, उसके लिए अलग-अलग सिक्योरिटी फोर्सेज की विशेष 20 से अधिक टीमें अलग-अलग राज्यों के लिए तैयार की गई है, इन टीमों में बमनिरोधक दस्ते के साथ-साथ आधुनिक विस्फोटक ढूंढने की तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वहीं डॉग स्क्वायड टीम, जिसमें बेल्जियम मेलानॉइस किस्म के डॉग के साथ-साथ देसी मोहदुल डॉग को भी इृश्वष्ठ विस्फोटक ढूंढने में किया जा रहा है. मकसद ये है कि ऑपरेशन द एंड के तहत पूरी तरीके से नक्सली इलाके को हथियार और विस्फोटक से मुक्त करना है.

बस्तर में ऐतिहासिक परिवर्तन

नक्सलियों के काल पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुंदर राज पी पिछले कई सालों से नक्सली इलाके में तैनात हैं और एक बहुत बड़ा श्रेय इनको नक्सली मुक्त भारत में दिया जाएगा. आजतक से बातचीत में उन्होंने कहा कि मिशन 2026 के तहत बस्तर आज एक ऐतिहासिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है. लंबे समय तक हिंसा और भय के साये में रहा ये क्षेत्र अब शांति, विश्वास और विकास की नई दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहा है. सुरक्षा बलों, स्थानीय प्रशासन और बस्तर की जनता के संयुक्त संकल्प ने नक्सल-मुक्त बस्तर के लक्ष्य को लगभग साकार कर दिया है.

अब बस्तर का विकास प्राथमिकता

छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि राज्य में हथियारबंद नक्सली कैडर 'पूरी तरह से समाप्त' हो गया है और अब मुख्य चुनौती पर्यावरण तथा आदिवासी संस्कृति के संरक्षण के साथ बस्तर का विकास है। शर्मा ने यह भी कहा कि दो वर्ष पहले नक्सलवाद को खत्म करने के लिए स्पष्ट समयसीमा तय करना, तकनीक आधारित खुफिया तंत्र और सुरक्षा बलों द्वारा सटीक अभियान ने इस दिशा में अहम भूमिका निभाई। गृह विभाग भी संभाल रहे शर्मा ने सोमवार शाम दिए इंटरव्यू में कहा कि सरेंडर करने वाले नक्सलियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने का निर्णय राष्ट्रीय स्तर पर लिया जाएगा। शर्मा ने कहा, हथियारबंद नक्सलवाद से मुक्ति का जो विषय था, वह अब पूरा हो चुका है। छत्तीसगढ़ में सशस्त्र नक्सलियों का पूरा कैडर समाप्त हो गया है। आज जब हम बात कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि जो 15-20 नक्सली शेष हैं, वे भी पुनर्वास की प्रक्रिया में हैं। 31 मार्च 2026 की निर्धारित समयसीमा तक राज्य में नक्सली संगठन का सशस्त्र कैडर पूरी तरह समाप्त हो चुका है।

संविधान का शासन बस्तर और राज्य के हर कोने तक पहुंचा

उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ में नक्सली संगठन असल में खत्म हो चुका है। इसे पिछले दो वर्षों की 'सबसे बड़ी उपलब्धि' बताते हुए शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व को इसका श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि इनके प्रयासों से संविधान का शासन बस्तर और राज्य के हर कोने तक पहुंचा है। उन्होंने कहा, 'नक्सल विरोधी अभियान इतने सटीक थे कि सुरक्षा कर्मियों को खरोंच तक नहीं आई, जबकि कई नक्सली मारे गए। पिछले दो वर्षों में हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि नक्सलवाद पर नियंत्रण पाना रही है।'

जनता का भरोसा बनने तक सुरक्षा शिविर जारी रहेंगे

बस्तर में सुरक्षा बलों की तैनाती का जिक्र करते हुए शर्मा ने कहा कि सुरक्षा शिविर फिलहाल जारी रहेंगे, क्योंकि जनता का भरोसा बनने में समय लगता है। उन्होंने कहा कि यह सच है कि पूरा कैडर खत्म हो चुका है, लेकिन लोगों को इसे पूरी तरह स्वीकार करने में समय लगेगा। एहतियाती इंतजाम जारी रहेंगे। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि अंदरूनी इलाकों में मौजूद करीब 400 सुरक्षा शिविरों को धीरे-धीरे पुलिस थानों, स्कूलों, अस्पतालों या पंचायत भवनों जैसे आधारभूत ढांचों में बदला जाएगा। शर्मा ने याद दिलाया कि 10 मार्च को विधानसभा के बजट सत्र में उन्होंने कहा था कि बस्तर में तैनात अधिकांश अर्धसैनिक बलों को 31 मार्च 2027 तक वापस बुलाया जा सकता है।

भूपेश बघेल पर साधा निशाना

शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा, 'पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे थे कि 31 मार्च आ गया है, चलो जश्न मनाते हैं। मैं आपको बता दूं, यह नए साल की शाम नहीं है। आपको यह समझना होगा कि यह एक गंभीर विषय है।'

बस्तर में अब सबसे बड़ी चुनौती विकास

उन्होंने कहा कि अगर नक्सली नेटवर्क पूरी तरह समाप्त हुआ है, तो यह केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए बड़ी उपलब्धि है। आखिर, एक समय देश में होने वाली 80 प्रतिशत नक्सली गतिविधियां छत्तीसगढ़ में केंद्रित थीं। शर्मा ने कहा कि बस्तर में अब सबसे बड़ी चुनौती विकास की है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण, आदिवासी संस्कृति को बचाए रखना और युवाओं के लिए आर्थिक अवसर सृजित करना शामिल है।

क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाएगा

उन्होंने कहा कि लघु वनोपज और महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। बस्तर के विकास की रूपरेखा पर उन्होंने कहा कि भले ही कोई तय खाका नहीं है, लेकिन दिशा स्पष्ट है। बस्तर में विकास खासकर राज्य के आदिवासी-बहुल सरगुजा क्षेत्र के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है, जहां विकास की गुंजाइश पूरी तरह से खत्म हो जाए। उन्होंने कहा कि विकास एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, चाहे वह बस्तर में हो या सरगुजा में। विकास की कमी और हथियार उठाने के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है।

बस्तर को बदलने के लिए निरंतर प्रयास जरूरी

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक-आर्थिक समस्याएं लोगों को हथियार उठाने के लिए प्रेरित नहीं करतीं। शर्मा ने कहा कि बस्तर को बदलने के लिए निरंतर प्रयास जरूरी हैं और यहां के युवाओं में अपार प्रतिभा है। उन्होंने कहा, हमें बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी और बस्तर के विकास के लिए अभी और भी बहुत कुछ करना बाकी है। मेरा विश्वास है कि बस्तर के युवाओं में इतनी जबर्दस्त प्रतिभा है कि अगर 2036 के ओलंपिक खेलों में बस्तर का कोई युवा देश के लिए कोई पदक जीत लाए, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी। उन्होंने कहा, 'इसके अलावा, बस्तर की महिलाएं-हमारी माताएं और बहनें-सही मायने में भविष्य में इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार बनेंगे।'

बस्तर विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ेगा

शर्मा ने कहा, 'मुझे पूरा विश्वास है कि महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ये महिलाएं इस क्षेत्र में सफलतापूर्वक बड़े उद्यम स्थापित करेंगी। जैसे-जैसे हम अपने प्रयास जारी रखेंगे, बस्तर विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा और इसके युवा वैश्विक मंच पर अपनी छाप छोड़ते हुए नजर आएंगे।' उन्होंने कहा कि बस्तर की अर्थव्यवस्था का आधार लघु वनोपज होगा और इस दिशा में काम पहले से जारी है। खनन गतिविधियों को लेकर फैल रही अफवाहों पर उन्होंने कहा कि इनमें कोई सच्चाई नहीं है और सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। तेलंगाना के संदर्भ में उन्होंने कहा कि वहां की सरकार ने भी नक्सलवाद के खिलाफ प्रभावी काम किया है और उसे 'नरम रवैया' कहना सही नहीं होगा।

नक्सलियों के खिलाफ मामले वापस क्या बोले विजय शर्मा

सरेंडर करने वाले नक्सलियों के राजनीति में आने के सवाल पर शर्मा ने कहा कि संविधान सभी नागरिकों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने की स्वतंत्रता देता है, बशर्ते वे हिंसा का रास्ता छोड़ दें। इस सवाल पर कि क्या सरेंडर करने वाले नक्सलियों के खिलाफ मामले वापस लिए जाएंगे, उन्होंने कहा, 'यह एक राष्ट्रीय स्तर का नीतिगत निर्णय है। हमें इन सभी पहलुओं पर विचार करना होगा, क्योंकि उन्होंने सरेंडर कर दिया है, अपने हथियार डाल दिए हैं और मुख्यधारा में लौट आए हैं। कोई भी निर्णय राष्ट्रीय स्तर पर ही लिया जाना चाहिए।' उन्होंने कहा कि राज्य की औद्योगिक नीति में उन कंपनियों को प्रोत्साहन देने का प्रावधान है जो पुनर्वासित नक्सलियों को रोजगार देती हैं, और सरकार ऐसे लोगों की सूची उद्योगों के साथ साझा कर सकती है।

होर्मुज की लहरों में डूबता सुपर पावर का गुमान

अजय कुमार

इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि युद्ध के मैदान में जब बंदूकें खामोश होने लगती हैं, तब झूठ के नगाड़े सबसे जोर से बजते हैं। आज फारस की खाड़ी के तपते पानी में जो कुछ घट रहा है, वह किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है, लेकिन इस पटकथा का अंत वैसा नहीं है जैसा वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस में बैठकर लिखा गया था। युद्ध में कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, इसे आंकने का पैमाना कभी भी मिसाइलों की संख्या या मलबे का ढेर नहीं होता। इसका सबसे सटीक पैमाना यह है कि शांति की भीख सबसे पहले किसने मांगी। आज जब हम अप्रैल 2026 की दहलीज पर खड़े हैं, तो दुनिया देख रही है कि जिस ईरान को प्रतिबंधों की बेड़ियों में जकड़कर घुटनों पर लाने का दावा किया गया था, वह आज तनकर खड़ा है और दुनिया का स्वयंभू थानेदार अब एग्जिट गेट की तलाश में हाथ-पांव मार रहा है।

इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे मुड़कर साल 2025 के उस 'ऑपरेशन सिंदूर' को देखना होगा, जिसने उपमहाद्वीप के सैन्य इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। भारत ने जब अपनी सीमा पार कर आतंकवाद के फनों को कुचला, तो वह केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक संदेश था। वह संदेश यह था कि शक्ति प्रदर्शन चीखने-चिल्लाने से नहीं, बल्कि सटीक प्रहार से होता है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम जब ताश के पत्तों की तरह ढह रहा था और भारतीय विमान आकाश में अपनी मर्जी से चित्रकारी कर रहे थे, तब रावलपिंडी के जनरलों ने पहली बार शांति का राग अलापा था। वह हार की तड़प थी जिसे जीत के पदकों के पीछे छिपाने की नाकाम कोशिश की गई। आसिम मुनीर का खुद को 'फील्ड मार्शल' घोषित कर देना वैसा ही था जैसे कोई डूबता हुआ आदमी खुद को समंदर का राजा कह दे। लेकिन गड्ढे झूठ नहीं बोलते। सैटेलाइट की तस्वीरों ने वह सच दुनिया के सामने रख दिया था जिसे पाकिस्तान की पीआर मशीनरी दबाना चाहती थी।

आज मिडिल ईस्ट के रणक्षेत्र में डोनाल्ड ट्रंप वही गलती दोहरा रहे हैं जो कभी पाकिस्तानी जनरलों ने की थी। 28 फरवरी को जब ईरान के शीर्ष नेतृत्व पर हमला हुआ, तो अमेरिका को लगा कि तेहरान ताश की गड्डी की तरह बिखर जाएगा। लेकिन वे भूल गए कि जिस देश ने 40 साल से प्रतिबंधों की आग में खुद को तपाया हो, उसके लिए मिसाइलों की गड़गड़ाहट किसी उत्सव से कम नहीं होती। ईरान ने पलटवार किया और ऐसा किया कि पूरे मध्य पूर्व में फैले अमेरिकी अड्डों की सुरक्षा की कलई खुल गई। आज होर्मुज स्ट्रेट बंद है। दुनिया की रगों में दौड़ने वाला तेल अब ईरान की मर्जी का मोहताज है। वह देश जो कल तक दूसरे देशों को सुरक्षा की गारंटी बेचता था, आज अपने ही सैनिकों की जान बचाने के लिए उन रास्तों को ढूंढ रहा है जो तेहरान तक जाते हों।

ट्रंप का आज का अंदाज बिल्कुल मई 2025 के पाकिस्तान जैसा है। कैमरों के सामने आकर वे अपनी जीत के कसीदे पढ़ रहे हैं, ट्रुथ सोशल पर कैप्स लॉक में अपनी ताकत का बखान कर रहे हैं, लेकिन जमीन की हकीकत उनके दावों का मजाक उड़ा रही है। जब आप हार रहे होते हैं, तो आपकी भाषा में अहंकार और हताशा का एक अजीब मिश्रण घुल जाता है। अमेरिका आज पाकिस्तान के जरिए ईरान को 15 सूत्रीय प्रेम पत्र भेज रहा है, लेकिन तेहरान ने साफ कर दिया है कि वह किसी सेल्समैन से बात नहीं करेगा। ईरान की शर्तें साफ हैं होर्मुज पर उसका नियंत्रण होगा, अमेरिकी फौजें इलाका खाली करेंगी और नुकसान की भरपाई वॉशिंगटन को करनी होगी। ये शर्तें किसी हारे हुए राष्ट्र की नहीं, बल्कि उस खिलाड़ी की हैं जिसने सामने वाले की पूरी बिसात उलट दी है।

मिडिल ईस्ट में अमेरिका की विफलता केवल सैन्य नहीं, बल्कि रणनीतिक और नैतिक भी है। जिस रडार और एयर डिफेंस के भरोसे अमेरिका अपनी धौंस जमाता था, वे आज मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। अरब देश, जो कभी अमेरिका की छत्रछाया में खुद को सुरक्षित महसूस करते थे, अब नए समीकरणों की तलाश में हैं। सऊदी अरब का यूक्रेन के साथ डिफेंस डील करना इस बात का सीधा प्रमाण है कि अब दुनिया को ट्रंप के कार्ड्स की असलियत समझ आ गई है। जब घर का मुखिया ही चोरों से अपनी रक्षा न कर पाए, तो परिवार के बाकी सदस्य नए रक्षक ढूंढने लगते हैं। आज वही स्थिति अमेरिका की है।

सबसे दिलचस्प भूमिका पाकिस्तान की है, जो अपनी फटेहाली को कूटनीतिक अवसर में बदलने की कोशिश कर रहा है। वह देश जिसने खुद अपनी नाक कटवाई थी, आज अमेरिका और ईरान के बीच बिचौलिए की भूमिका में डॉलर बटोरने के सपने देख रहा है। लेकिन ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इस खेल का हिस्सा नहीं बनेगा। ईरान जानता है कि वक्त उसके साथ है। वह चुप है, शांत है और अपने लक्ष्यों के प्रति अडिग है। उसकी यह खामोशी वॉशिंगटन की बेचैनी को और बढ़ा रही है। जब आपके पास खोने के लिए कुछ न बचा हो, तो आप सबसे खतरनाक योद्धा बन जाते हैं। ईरान आज उसी स्थिति में है।

कार्ल मार्क्स ने सच ही कहा था कि इतिहास खुद को दोहराता है, पहले एक त्रासदी के रूप में और फिर एक मजाक के रूप में। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के लिए त्रासदी थी, और आज फारस की खाड़ी में अमेरिका जो कर रहा है, वह एक वैश्विक मजाक बनकर रह गया है। ट्रंप अब एक सुरक्षित रास्ता ढूंढ रहे हैं जिससे वे अपनी साख बचा सकें, लेकिन ईरान उन्हें वह मौका देने के मूड में नहीं है। वह होर्मुज का पूरा टोल वसूलने के बाद ही चैन से बैठेगा। यह युद्ध मिसाइलों से नहीं, बल्कि सब्र और हौसले से जीता जा रहा है। और फिलहाल, जीत का सेहरा तेहरान के सिर बंधता दिख रहा है, जबकि वॉशिंगटन की चमकती वर्दी पर धूल और हार की कालिख साफ देखी जा सकती है। गड्ढे आज भी वहीं हैं, चाहे वो रावलपिंडी के एयरफील्ड पर हों या ट्रंप की विदेश नीति के सीने पर। सच तो यही है कि सुपरपावर का गुमान अब फारस की खाड़ी की लहरों में दफन हो चुका है।

राजनीति को बदल देगा महिला आरक्षण

लेकिन इस कदम को सिर्फ चुनावी राजनीति के चश्मे से देखना सही नहीं होगा. लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में बहुप्रतीक्षित महिला आरक्षण लागू हो जाता है, तो यह भारतीय राजनीति की एक बड़ी उपलब्धि होगी.

नीरजा चौधरी

पिछले सप्ताह केंद्र सरकार ने अचानक नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण) के तहत संसद और विधानसभाओं में 33 फीसदी महिला आरक्षण के लिए संविधान संशोधन से संबंधित तैयारी शुरू की. उसने इसके लिए विपक्ष से सहयोग मांगा है. बताया यह जा रहा है कि विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाने के बाद संसद का विशेष सत्र बुलाकर संविधान संशोधन विधेयक पारित किया जायेगा. इसमें कई सारे कदम उठाये जाने की बात कही गयी है. जैसे- संविधान संशोधन से लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 816 हो जाने वाली हैं, जिनमें से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जायेंगी.

इसके अलावा, सरकार ने परिसीमन को 2026-27 के बजाय 2011 की जनगणना के आधार पर कराने का फैसला किया है. इसके पीछे तर्क यह है कि नयी जनगणना होने और उसका आंकड़ा आने में इतना समय लग जायेगा कि 2029 के लोकसभा चुनाव तक परिसीमन नहीं हो पायेगा. एक और प्रस्ताव यह है कि संशोधन से राज्यों में सीटों की वृद्धि का अनुपात नहीं बदलेगा. जबकि पहले ऐसा माना जा रहा था कि कम जनसंख्या होने के कारण दक्षिण भारत के राज्यों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा.

इस कारण दक्षिण के नेता क्षुब्ध थे. लेकिन नये प्रस्ताव के मुताबिक, परिसीमन से उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें 80 से बढ़कर अगर 120 हो जायेंगी, तो तमिलनाडु में भी लोकसभा सीटों में वृद्धि इसी अनुपात में होगी. परिसीमन के मुद्दे पर लंबे समय से उत्तर बनाम दक्षिण का न सिर्फ द्वंद्व छिड़ा हुआ था, बल्कि दक्षिण के राज्यों को लगता था कि जनसंख्या को नियंत्रित रखने का उन्हें दंड दिया जा रहा है, जबकि ज्यादा आबादी वाले उत्तर भारत के राज्यों को परिसीमन के जरिये बड़ा राजनीतिक लाभ मिलेगा. लेकिन नये प्रस्ताव में यह आशंका दूर हो गयी है.

दरअसल, परिसीमन मुद्दे पर एनडीए में भाजपा के सहयोगी चंद्रबाबू नायडू तक का रवैया नाराजगी भरा था, और वैसे में, दक्षिण भारत में भाजपा के लिए अपना विस्तार कर पाना कठिन होता, इसलिए 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन कराकर दक्षिण की आशंकाओं को दूर करने की कोशिश है. दरअसल, 19 सितंबर, 2023 को जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण) संसद से पारित हुआ था, तब इसे जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन और 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू करने की घोषणा की गयी थी. लेकिन अब सरकार ये दोनों कार्य संविधान संशोधन के जरिये करना चाहती है. संविधान संशोधन के लिए संसद में दो-तिहाई बहुमत चाहिए, जो सरकार के पास नहीं है. इसके अलावा, आधे राज्यों को इसे पारित कराना होगा. बेशक मौजूदा राजनीतिक माहौल में इसे पारित कराना आसान नहीं है. लेकिन विपक्षी दल महिला आरक्षण का विरोध भी नहीं कर पायेंगे.

अगर संसद के विशेष सत्र में इस पर मुहर लग जाती है, तो फिर परिसीमन आयोग बैठेगा, और उम्मीद की जानी चाहिए कि अगले वर्ष तक महिला आरक्षण लागू हो जायेगा. हालांकि यह सवाल उठाया जा रहा है कि महिला आरक्षण को अगर 2011 की जनगणना और परिसीमन के आंकड़ों पर ही लागू करना था, तो इसे पहले भी लाया जा सकता था. लेकिन सरकार अब अचानक यह कदम उठाने जा रही है, तो कुछ सोच-समझकर ही उठा रही होगी. दरअसल, अगले साल तीन राज्यों-उत्तर प्रदेश, गुजरात और पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. ये चुनाव, जाहिर है कि भाजपा और एनडीए के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं.

अगर अगले साल तक महिला आरक्षण लागू हो जाता है, तो इन तीनों राज्यों में भाजपा को चुनावी लाभ मिलना तय है. फिर 2029 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को इसका लाभ मिलेगा. हालांकि फिलहाल यह प्रस्ताव है, और काफी जटिल भी है. कई प्रश्नों के जवाब अभी तक नहीं मिले हैं. जैसे परिसीमन के बाद लोकसभा में महिलाओं के लिए 273 सीटें आरक्षित हो जायेंगी. लेकिन ये सीटें किस तरह आरक्षित होंगी, इस बारे में अभी कुछ तय नहीं है. सवाल यह भी है कि परिसीमन जब 2011 की जनगणना के आधार पर ही होना है, तो फिर 2026-27 की जनगणना के आधार पर नये सिरे से परिसीमन कराने का क्या औचित्य होगा. फिलहाल लगता है कि पश्चिम एशिया संकट को देखते हुए सरकार ने यह दांव चला है.

दरअसल युद्ध का लंबा असर रहने वाला है, और हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव भी लंबे समय तक रहेगा. इस कारण आय से लेकर रोजगार तक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में, महिला आरक्षण लागू कर सरकार महिलाओं का एकमुश्त वोट अपने साथ होने की उम्मीद कर सकती है. इस मामले में दो बातों पर ध्यान देना चाहिए. एक यह कि चुनावों में महिला वोटरों की भूमिका अब पुरुष वोटरों के बराबर या उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होने लगी है. इसके अलावा, महिलाओं का बड़ा वर्ग पहले से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के साथ है. ऐसे में, अगर मान लें कि युद्ध के असर से युवा वर्ग सरकार से नाराज हो जाये, तो उसका चुनावी नतीजे पर बड़ा असर पड़ने की आशंका नहीं है. इसके अलावा, परिसीमन चूंकि 2011 के आंकड़े पर ही होना है, ऐसे में, दक्षिण भारत के नेता खुश हैं, और वहां भाजपा को नाराजगी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा.

लेकिन इस कदम को सिर्फ चुनावी राजनीति के चश्मे से देखना सही नहीं होगा. लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में बहुप्रतीक्षित महिला आरक्षण लागू हो जाता है, तो यह भारतीय राजनीति की एक बड़ी उपलब्धि होगी. हालांकि कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि महिला आरक्षण के कारण जिन पुरुष राजनेताओं को अपनी सीटें गंवानी पड़ेंगी, वे आरक्षित सीटों पर अपनी महिला रिश्तेदारों को बिठा सकते हैं.

नेपाल की नयी सरकार से उम्मीदें बहुत

बालेंद्र शाह नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गये हैं. विगत आठ सितंबर से पहले उन्हें नेपाल से बाहर कम लोग जानते थे. वर्ष 2012 में अपने पहले म्यूजिक एलबम से चर्चा में आये बालेंद्र शाह ने दस साल में अपनी छवि राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में आक्रोश को स्वर देने वाले रैप गायक की बनायी. उनके तेवर नेपाली स्वाभिमान जगाने वाले थे, जिसमें नेपाल को अंतरराष्ट्रीय दबाव से मुक्त कर एक सशक्त देश बनाने की आकांक्षा शामिल थी. यह सब तब हो रहा था, जब नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों के लंबे संघर्ष के बाद नेपाल से 2008 में राजशाही विदा हो चुकी थी. आम जनता को उम्मीद थी कि 2015 के नये संविधान और प्रतिनिधि सभा के लिए चुनाव के रास्ते मुख्यधारा के राजनीतिक दल एक समृद्ध नेपाल बनाने के सपने को जमीन पर उतारने में सफल होंगे. पर ऐसा कुछ हुआ नहीं.

वर्ष 2017 से 2025 के बीच गठबंधन सरकारों में सत्ता की अदला-बदली का खेल शेर बहादुर देउबा, केपी शर्मा ओली और पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' के बीच चलता रहा. ये तीनों पूर्व प्रधानमंत्री 2025 तक सत्तर की उम्र पार कर चुके थे और सत्ता के लोभ में इनके दलों की विचारधारा और सिद्धांत पीछे छूट रहे थे. अस्थायी सरकारों के उस दौर में नेपाल में बेरोजगारी, पलायन और आर्थिक असमानता बढ़ती गयी. नेताओं पर भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद के गहरे आरोप लगे. इसी बीच 2022 में बालेंद्र शाह ने जब युवाओं का आह्वान करते हुए, स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में मुख्य राजनीतिक दलों को दरकिनार कर काठमांडू में मेयर का चुनाव जीता और राजधानी में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाये, तो उनका राजनीतिक कद बढ़ गया. उन्होंने खुद को पुरानी पीढ़ी के राजनेताओं के विकल्प के रूप में पेश किया.

वर्ष 2022 में ही लोकप्रिय टीवी एंकर रवि लामिछाने ने कुछ उच्च शिक्षित युवाओं के साथ आरएसपी यानी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की और राजनीतिक चेहरे के रूप में उभरे. देश के युवा सोशल मीडिया पर भ्रष्ट राजनीतिक दलों और नेताओं के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार कर रहे थे. युवाओं के बढ़ते आक्रोश को रोकने के लिए सितंबर, 2025 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री केपीशर्मा ओली ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया, तो क्षुब्ध युवा सड़क पर उतर गये, सरकार को घुटने टेकने पड़े, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और देश को आम चुनाव में जाना पड़ा. सोशल मीडिया ने ही बालेंद्र शाह और सौदान गुरुंग जैसे युवाओं को सत्ता तक पहुंचाया है. इस महीने हुए चुनाव में बालेंद्र शाह

चुनाव में आरएसपी की जीत और नेपाल की पारंपरिक पार्टियों की हार के बीच 'माध्यम', 'सोच' और 'नेतृत्वकर्ता' का फर्क साफ है. पर सरकार की आलोचना करने और सरकार चलाने में फर्क होता है.

को प्रधानमंत्री पद तक भी सोशल मीडिया ने ही पहुंचाया है.

बालेंद्र शाह को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाने के पीछे युवाओं के लिए रोजगार सृजन, देश की आर्थिक उन्नति और भ्रष्टाचार के खात्मे जैसे वादों की लंबी सूची है. चुनाव में आरएसपी की जीत और नेपाल की पारंपरिक पार्टियों की हार के बीच 'माध्यम', 'सोच' और 'नेतृत्वकर्ता' का फर्क साफ है. पर सरकार की आलोचना करने और सरकार चलाने में फर्क होता है. चुनाव में दो तिहाई बहुमत हासिल करने वाली नयी सरकार से उम्मीदें बहुत हैं और नेताओं पर अपने किये गये वादे पूरा करने का दबाव भी है. लाखों लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है, तो असंख्य लोग आर्थिक अवसर पाते ही देश में लौटना चाहते हैं. पर युद्ध और वैश्विक तनाव के बीच क्या नेपाल आर्थिक उन्नति का कोई नया मॉडल दिखा सकता है?

आर्थिक समृद्धि के लिए दूसरे देशों के साथ नेपाल के रिश्तों और व्यापार की शर्तों की अहम भूमिका होगी. अमेरिका-ईरान युद्ध के चलते बालेंद्र शाह की सरकार को अतिरिक्त संकट का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि नेपाल की बड़ी आबादी खाड़ी देशों में काम करती है और नेपाल की जीडीपी में खाड़ी देशों से आने वाले रेमिटेंस की हिस्सेदारी करीब तीस फीसदी है. अंतरराष्ट्रीय मंच पर उभार के साथ यह भी संभव है कि बालेंद्र शाह पड़ोसी देशों के साथ कुछ मुद्दों पर अब अलग स्टैंड लें. नेपाल के साथ ऐतिहासिक संबंधों के चलते भारत सरकार काठमांडू के साथ सहयोग के लिए सदैव तत्पर रहती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालने पर बालेंद्र शाह को न सिर्फ बधाई दी है, बल्कि दोनों देशों के बीच बेहतर रिश्तों की उम्मीद भी जताई है. भारत-नेपाल के बीच खुली सीमा के साथ नेपाल में एक मजबूत सरकार बनने से सीमा के आर-पार अपराध, तस्करी और अवैध कारोबार को रोकने में मदद मिलेगी. भारत और नेपाल बिजली उत्पादन, कृषि ,शिक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा सकते हैं.

अपने शपथ ग्रहण समारोह में बालेंद्र शाह ने जिस तरह हिंदू और बौद्ध परंपरा के मंत्रोचार और शंखनाद को शामिल किया है, उससे स्पष्ट है कि वह नेपाल की मध्यमार्गी राजनीति के साथ अपना विस्तार करना चाहते हैं. प्रधानमंत्री के रूप में बालेंद्र शाह की भूमिका और पड़ोसी देशों के साथ उनकी सरकार के रिश्तों का मूल्यांकन तो आने वाला समय बतायेगा, लेकिन घरेलू राजनीति भी उनके लिए चुनौतियों से भरी है. आरएसपी के प्रमुख रवि लामिछाने के साथ तालमेल बिठाने के साथ उन पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने का दबाव भी उन पर होगा. जेन जी आंदोलन के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए गठित आयोग की रिपोर्ट पर नयी सरकार क्या कार्रवाई करती है, यह देखना होगा, लेकिन सरकार गठन के अगले ही दिन पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व मंत्री रमेश लेखक की गिरफ्तारी से नयी सरकार पर सवाल उठने शुरू हो गये हैं और विपक्षी राजनीतिक पार्टियां इसे बदले की भावना से की गयी कार्रवाई बता रही हैं. ऐसे में, सरकार के खिलाफ संसद से सड़क तक राजनीतिक आंदोलन होने की आशंका भी बढ़ गयी है.

ऐसे में, सोशल मीडिया पर सक्रिय युवाओं को धैर्य के साथ देखना होगा कि पार्टी और सरकार के बीच तालमेल कैसे बैठता है तथा पार्टी कैसे एकजुट रहती है. नेपाल के सभी इलाकों के लोगों को सेना, पुलिस और अन्य रोजगार क्षेत्रों में समान अवसर मिले, सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा. नेपाल के मीडिया को इस नये प्रयोग को उम्मीद से देखना होगा कि अगले बारह महीने तक इस सरकार का रुझान क्या रहता है. आने वाला समय बतायेगा कि क्या वास्तव में नेपाल में बिना भ्र्ष्टाचार के विकास का मार्ग प्रशस्त हो रहा है अथवा राजनीति की नयी पिच और प्रयोग भी कुछ नये अभिजनों के उभार तक सीमित रहते हैं?

जल संरक्षण का 5% मॉडल: कोरिया मॉडल (एरियल व्यू)

जल संरक्षण का कोरिया मॉडल बना राष्ट्रीय उदाहरण

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने की सराहना, बताया जनभागीदारी आधारित जल संरक्षण का प्रेरक उदाहरण

कोरिया जिले में जल संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देते हुए 'कैच द रेन' तथा राज्य शासन के मोर गाव मोर पानी महा अभियान अभियान के अंतर्गत में 'आवा पानी झोंकी' अभियान संचालित किया गया। इस पहल ने जल संरक्षण को केवल एक सरकारी योजना से आगे बढ़ाकर व्यापक जनभागीदारी पर आधारित आंदोलन बना दिया है।

इस अभिनव प्रयास को राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान तब मिली, जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने लोकप्रिय कार्यक्रम 'मन की बात' में कोरिया मॉडल की सराहना की और इसे जनभागीदारी आधारित जल संरक्षण का प्रेरक उदाहरण बताया।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय स्तर पर भी इस मॉडल को सराहना प्राप्त हुई है। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सी आर पाटिल द्वारा भी कोरिया मॉडल को अन्य राज्यों में लागू किए जाने योग्य पहल के रूप में उल्लेखित किया गया, जिससे इसकी उपयोगिता और विस्तार की संभावनाएँ स्पष्ट होती हैं।

कोरिया जिले में लगभग 1370 मिमी वार्षिक वर्षा होने के बावजूद भू-आकृतिक परिस्थितियों के कारण जल का तीव्र बहाव होता था, जिससे भूजल पुनर्भरण सीमित था।

कोरिया मॉडल- जन आंदोलन की अवधारणा

'जल संचय जन भागीदारी अभियान' के अंतर्गत लागू 5% मॉडल के तहत किसानों ने अपनी भूमि का 5% भाग छोटी सीढ़ीदार जल संरचनाओं के लिए समर्पित किया साथ ही सोखता गड्ढे और मनरेगा के अंतर्गत संरचनाएं बनाई गईं।

सामुदायिक एवं वैज्ञानिक समन्वय

महिलाओं ने नीर नायिका, युवाओं ने जल दूत के रूप में भूमिका निभाई और ग्राम सभाओं के माध्यम से विकेंद्रीकृत योजना को सशक्त बनाया। इससे समुदाय स्वयं कार्यान्वयनकर्ता बना।

2025 की उपलब्धियाँ (जल पुनर्भरण)

जिले में कुल लगभग 2.8 MCM (28 लाख घन मीटर) जल का भूजल में पुनर्भरण हुआ। यह जल मात्रा लगभग 230–235 (12000 m^3/ तालाब) बड़े तालाबों के बराबर और 1800 से अधिक (1500 m^3/ डबरी) डबरियों के बराबर है। (गणनाएं मानक वैज्ञानिक मानकों एवं सावधानीपूर्वक किए गए आकलन पर आधारित हैं।)

भूजल स्तर में सुधार

CGWB की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में कोरिया जिले के भूजल स्तर में 5.41 मीटर की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, जो इस मॉडल की प्रभावशीलता को दर्शाती है।

20,612 से अधिक जल संरक्षण कार्य पूर्ण/प्रगति पर हैं जिनके अंतर्गत 17,229 सामुदायिक कार्य तथा 3,383 मनरेगा आधारित संरचनाएँ शामिल हैं।

जिला कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी ने कहा— कोरिया मॉडल की सफलता का मूल आधार जनभागीदारी है। जब समाज स्वयं जल संरक्षण का संकल्प लेता है, तो परिणाम स्थायी और व्यापक होते हैं। हमारा प्रयास है कि हर बूंद को संजोकर आने वाली पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

कोरिया मॉडल यह प्रमाणित करता है कि जब जनभागीदारी, वैज्ञानिक योजना, शासन और प्रशासनिक नेतृत्व एक साथ कार्य करते हैं, तो जल संरक्षण को एक स्थायी जन आंदोलन में परिवर्तित किया जा सकता है— और यही मॉडल अब राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनाए जाने की दिशा में अग्रसर है।

बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट से रात्रि उड़ान सेवा का शुभारंभ

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भरी पहली नाइट फ्लाइट

बिलासपुर के बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट से रात्रि उड़ान सेवा की ऐतिहासिक शुरुआत हो गई। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने नाइट ऑपरेशन्स का लोकार्पण किया और इसी दौरान स्वयं रात में पहली उड़ान से रायपुर के लिए रवाना हुए। विधायक श्री धर्मजीत सिंह भी मुख्यमंत्री जी के साथ रात्रिकालीन उड़ान में रायपुर गए।

उल्लेखनीय है कि एयरपोर्ट को 3सी वीएफआर से उन्नत कर 3सी आईएफआर श्रेणी में विकसित करने का कार्य लगभग 31 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण किया गया। इस उन्नयन के बाद डीजीसीए के द्वारा 6 फरवरी 2026 को एयरपोर्ट को 3सी आईएफआर श्रेणी में रात्रिकालीन संचालन की अनुमति प्रदान की गई, जिससे अब यहां रात में भी उड़ानों का संचालन संभव हो सका है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि रात्रि उड़ान सेवा शुरू होने से अब निर्धारित उड़ानों के साथ-साथ आपातकालीन एवं मेडिकल फ्लाइट्स भी रात में संचालित हो सकेंगी, जिससे जीवनरक्षक सेवाएं और अधिक प्रभावी होंगी। बेहतर हवाई संपर्क से व्यापार, पर्यटन और निवेश को बढ़ावा मिलेगा तथा क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी। उन्होंने नागरिकों से इस नई सुविधा का अधिकतम लाभ उठाने की अपील करते हुए सभी यात्रियों के लिए सुरक्षित और सुखद यात्रा की कामना की। समारोह को केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू और विधायक श्री धरमलाल कौशिक ने भी संबोधित किया।

अंबिकापुर से दिल्ली-कोलकाता के लिए डायरेक्ट फ्लाइट सेवा

नई हवाई सेवा के अंतर्गत एलायंस एयर द्वारा 72-सीटर एटीआर विमान संचालित किया जाएगा। अंबिकापुर से दिल्ली के लिए फ्लाइट हफ्ते में दो दिन सोमवार और बुधवार को चलेगी। सोमवार को फ्लाइट सुबह 7.50 बजे दिल्ली से उड़ान भरकर 10.25 बजे बिलासपुर पहुंचेगी, वहां से 10.50 बजे रवाना होकर 11.35 बजे अंबिकापुर पहुंचेगी। इसके बाद यही फ्लाइट दोपहर 12.05 बजे अंबिकापुर से उड़ान भरकर 2.35 बजे दिल्ली पहुंचेगी। बुधवार को सुबह 7.50 बजे दिल्ली से सीधी फ्लाइट उड़कर 10.25 बजे अंबिकापुर पहुंचेगी, फिर 10.50 बजे अंबिकापुर से निकलकर 11.35 बजे बिलासपुर पहुंचेगी और वहां से 12.00 बजे उड़कर 2.40 बजे दिल्ली पहुंचेगी।

अंबिकापुर से कोलकाता के लिए भी हफ्ते में दो दिन फ्लाइट चलेगी। शनिवार को सुबह 7.05 बजे कोलकाता से फ्लाइट उड़ान भरकर 8.55 बजे बिलासपुर पहुंचेगी, फिर 9.20 बजे वहां से रवाना होकर 10.00 बजे अंबिकापुर पहुंचेगी। इसके बाद 10.25 बजे अंबिकापुर से उड़कर 12.15 बजे कोलकाता पहुंच जाएगी। वहीं गुरुवार को सुबह 7.05 बजे कोलकाता से सीधी फ्लाइट उड़कर 8.50 बजे अंबिकापुर पहुंचेगी, फिर 9.15 बजे अंबिकापुर से निकलकर 9.55 बजे बिलासपुर पहुंचेगी और वहां से 10.20 बजे उड़कर 12.05 बजे कोलकाता पहुंचेगी।

निर्धारित शेड्यूल के तहत यात्रियों को आने-जाने दोनों दिशाओं में सुविधा उपलब्ध होगी तथा बिलासपुर क्षेत्र की कनेक्टिविटी भी सुदृढ़ होगी। कोलकाता के लिए भी विमान सेवा प्रारंभ होने से पूर्वी भारत के प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र से सीधा संपर्क स्थापित होगा, जिससे क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को नया विस्तार मिलेगा।

अम्बिकापुर सरगुजा संभाग का मुख्यालय होने के साथ उत्तर छत्तीसगढ़ का प्रमुख प्रशासनिक, शैक्षणिक एवं वाणिज्यिक केंद्र है।

कम उम्र में अनाथ हुए मिजोरम के किशोर इसाक : मालसावमटलुआंगा ने चोट की चिंता को पीछे छोड़कर जीता केआईटीजी स्वर्ण

इसाक ने 2018 में अपने पिता और 2024 में अपनी मां को खो दिया

केआईटीजी से पहले पीठ की चोट से जूझने के बावजूद क्लीन एंड जर्क में शानदार प्रदर्शन कर जीता स्वर्ण पदक

मिजोरम के युवा वेटलिफ्टर इसाक मालसावमटलुआंगा 16 साल की उम्र पूरी करने से पहले ही अपने माता-पिता दोनों को खोने के बाद लगभग खेल छोड़ने की कगार पर पहुंच गए थे। इस दोहरी त्रासदी ने इस मिजो किशोर को अंदर तक तोड़ दिया था, लेकिन उनके बचपन के कोच और चाचा-चाची के सहारे ने उनके खेल करियर को संभाल लिया। 18 वर्षीय इसाक ने कड़ा संघर्ष करते हुए खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में पुरुषों के 60 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर अपने परिवार को गर्व महसूस कराया।

पीठ की तकलीफ से जूझते हुए भी इसाक ने क्लीन एंड जर्क में शानदार प्रदर्शन किया। स्नैच में दूसरे स्थान पर रहने के बाद उन्होंने कुल 235 किग्रा वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। जीत के तुरंत बाद उनके चाचा ने उन्हें गले लगा लिया, जो इस युवा खिलाड़ी के जीवन में एक मार्गदर्शक की तरह रहे हैं।

इसाक के पिता हेमिंग मालसावमटलुआंगा की 2018 में एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, उसी साल उन्होंने वेटलिफ्टिंग की शुरुआत की थी। परिवार के इकलौते बेटे होने के कारण उनके सामने यह सवाल खड़ा हो गया था कि वह खेल जारी रखें या परिवार की जिम्मेदारियां संभालने के लिए कमाई पर ध्यान दें। इसाक ने साई मीडिया से बातचीत में बताया, उस समय मेरे बचपन के कोच सोमा ने मुझे बहुत प्रेरित किया और वेटलिफ्टिंग जारी रखने के लिए कहा।

हालांकि, 2024 में हिमाचल प्रदेश में आयोजित यूथ नेशनल चैंपियनशिप में 60 किग्रा वर्ग में रजत पदक जीतने के बाद जब उनका प्रदर्शन बेहतर होने लगा, तभी एक और निजी झटका लगा। उनकी मां को कैंसर का पता चला, जिससे परिवार पर भावनात्मक और आर्थिक दबाव बढ़ गया।

इस कठिन समय में उनके चाचा और चाची ने उनका सहारा बना। आइजोल के रामह्लुन वेंगथर इलाके में एक छोटे से रेस्तरां में काम करने वाला यह दंपति इसाक को अपने साथ ले आया और उसकी पढ़ाई और वेटलिफ्टिंग दोनों को बिना रुकावट जारी रखने में मदद की।

लेकिन उसी साल उनकी मां का निधन हो गया, जिसने इस युवा खिलाड़ी को पूरी तरह तोड़ दिया। कुछ समय के लिए वह खेल, जो कभी उसे उम्मीद देता था, उसके लिए बेमानी लगने लगा और अकेलापन व दुख उस पर हावी हो गयास उन्होंने कहा, अपने माता-पिता दोनों को खोना मुझे अंदर से पूरी तरह तोड़ गया था। मैंने लगभग तय कर लिया था कि वेटलिफ्टिंग छोड़ दूंगा, लेकिन मेरे चाचा और कोच ने एक बार फिर मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

2024 से इसाक इम्फाल स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में प्रशिक्षण ले रहे हैं और साथ ही आइजोल से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के जरिए कक्षा 12 की पढ़ाई भी कर रहे हैं।

धीरे-धीरे उनके प्रयास रंग लाने लगे। 2025 में मोदीनगर में आयोजित जूनियर प्रतियोगिता में उन्होंने एक और रजत पदक जीता और बाद में उसी वर्ष राष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया।

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स से पहले उनकी तैयारियों में भी चुनौतियां कम नहीं थीं। अभ्यास के दौरान उन्हें पीठ में चोट लग गई थी, जिसके चलते उनके कोच ने उन्हें टूर्नामेंट से दूर रहने की सलाह दी थी। लेकिन इसाक ने हार नहीं मानी और रायपुर में मंच पर उतरकर अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया।

वह कहते हैं, मेरे पिता के निधन के बाद से मेरे चाचा हमेशा प्रतियोगिताओं में मेरे साथ जाते हैं। वह यहां भी मेरे साथ थे। जैसे ही मैंने पदक जीता, उन्होंने मुझे अपनी बाहों में उठा लिया। उस पल मुझे एहसास हुआ कि वह कितने खुश थे। इसके बाद वह जश्न मनाने के लिए एक बार फिर अपने परिवार के पास लौट गए।

आधुनिक तकनीक के साथ संवेदनशीलता ही नई पुलिसिंग की पहचान

नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस अकादमी में 859 प्रशिक्षुओं का दीक्षांत समारोह

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज चंदखुरी स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी में आयोजित उप निरीक्षक संवर्ग के दीक्षांत (पासिंग आउट परेड) समारोह में शामिल हुए। उन्होंने परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। इस अवसर पर सूबेदार, उप निरीक्षक एवं प्लाटून कमांडर संवर्ग के अधिकारियों को सफल प्रशिक्षण पूर्ण करने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। इस सत्र में कुल 859 प्रशिक्षुओं ने प्रशिक्षण पूर्ण किया, जिनमें 54 सूबेदार, 528 उप निरीक्षक (जीडी), 02 उप निरीक्षक (कंप्यूटर), 01 उप निरीक्षक (रेडियो), 01 उप निरीक्षक (अंगुली चिन्ह), 68 उप निरीक्षक (एसबी) तथा 205 प्लाटून कमांडर शामिल हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने संबोधन में कहा कि यह दिन सभी प्रशिक्षुओं के जीवन का एक यादगार पड़ाव है, जहाँ से वे राष्ट्र और छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा के लिए संकल्पित होकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कठोर प्रशिक्षण के बाद प्राप्त यह उपलब्धि न केवल प्रशिक्षुओं के लिए, बल्कि उनके परिजनों और पूरे प्रदेश के लिए भी गर्व का विषय है। उन्होंने उल्लेख किया कि पिछले वर्ष जब उन्होंने इन्हीं युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए थे, तब उनके पास प्रतिभा थी, और आज प्रशिक्षण के बाद उनमें अनुशासन, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता का समावेश हो चुका है, जो उन्हें एक सफल अधिकारी बनाएगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने पुलिस सेवा को अत्यंत प्रतिष्ठित एवं जिम्मेदारीपूर्ण बताते हुए कहा कि किसी भी प्रतिष्ठित सेवा का आधार सत्यनिष्ठा होती है। उन्होंने प्रशिक्षुओं को प्रेरित करते हुए कहा कि पुलिस का मूल दायित्व नागरिकों की रक्षा करना है। जब भी कोई नागरिक असुरक्षित महसूस करता है, तो सबसे पहले पुलिस के पास ही जाता है। इसलिए जनता का विश्वास बनाए रखना पुलिस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि वर्दी केवल अधिकार नहीं, बल्कि जनता की सुरक्षा का संकल्प और उससे जुड़ी प्रतिष्ठा का प्रतीक है, जिसे हर परिस्थिति में बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी कभी आसान नहीं होती, लेकिन क्षमता और समर्पण के साथ इसे सफलतापूर्वक निभाया जा सकता है। प्रशिक्षण के दौरान किए गए कठिन परिश्रम की तरह ही सेवा में भी निरंतर प्रयास और समर्पण से संतोष और सफलता प्राप्त होती है।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आज का यह निष्क्रमण केवल अकादमी से बाहर निकलना नहीं, बल्कि वास्तविक कार्यक्षेत्र में प्रवेश का संकेत है। उन्होंने इसे सनातन परंपरा के 'निष्क्रमण संस्कार' से जोड़ते हुए बताया कि जैसे शिशु पहली बार घर से बाहर निकलता है, उसी प्रकार आज ये प्रशिक्षु सुरक्षित प्रशिक्षण वातावरण से निकलकर व्यापक जिम्मेदारियों वाले सेवा क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं।

छत्तीसगढ़ में पुलिसिंग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पुलिसिंग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। पिछले दो वर्षों में भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी एवं त्वरित

बनाया गया है, आधुनिक तकनीक और उपकरणों को पुलिस बल में शामिल किया गया है तथा साइबर अपराधों से निपटने के लिए विशेष इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। साथ ही प्रशिक्षण व्यवस्था को अधिक व्यावहारिक और आधुनिक स्वरूप दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य की पुलिस केवल कानून लागू करने वाली संस्था नहीं होगी, बल्कि एक सक्रिय सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करेगी, जिसके लिए उसे प्रतिक्रियात्मक से सक्रियात्मक एजेंसी में रूपांतरित होना होगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि देश वर्तमान में एक ऐतिहासिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, जिसमें औपनिवेशिक कानूनों के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसे नए कानून लागू किए गए हैं। यह दीक्षांत समारोह इस दृष्टि से विशेष महत्व रखता है कि यह उप निरीक्षकों का पहला बैच है, जिसने इन नवीन संहिताओं के तहत प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि ये अधिकारी इन कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करते हुए न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सुरक्षा, विकास और विश्वास इन तीन स्तंभों पर कार्य कर रही है और पुलिस की भूमिका इन तीनों को सशक्त बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पुलिस को केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि समाज से जुड़कर लोगों का विश्वास जीतना चाहिए, क्योंकि क्षेत्र डर से जीता जा सकता है, लेकिन दिल केवल विश्वास से ही जीता जा सकता है।

उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में स्मार्ट, तकनीक-संचालित और संवेदनशील पुलिस व्यवस्था की दिशा में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य की पुलिस डिजिटल, तकनीकी और उन्नत साधनों से लैस होगी, लेकिन जनता का विश्वास केवल व्यवहार, आचरण और निष्ठा से ही अर्जित किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब इन प्रशिक्षुओं का जीवन केवल व्यक्तिगत नहीं रहा, बल्कि समाज और राज्य की सेवा के लिए समर्पित हो गया है। उन्होंने सभी अधिकारियों से आह्वान किया कि वे प्रतिदिन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय न्याय, ईमानदारी और मानवता को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। अंत में उन्होंने सभी को इस उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि वे अपनी निष्ठा और समर्पण से छत्तीसगढ़ को सुरक्षित, सशक्त और समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि ये अधिकारी केवल कानून के रक्षक ही नहीं, बल्कि प्रदेश की आशाओं और विश्वास के संरक्षक भी हैं।

छत्तीसगढ़ पुलिस की ताकत को और सुदृढ़ करेंगे:विजय शर्मा

उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा ने इस अवसर पर प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके सभी उप निरीक्षकों एवं उनके परिजनों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये प्रशिक्षु छत्तीसगढ़ पुलिस की ताकत को और सुदृढ़ करेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में भर्ती प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संपन्न हुई है, जो शासन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे ऐसा वातावरण बनाएँ जिसमें अपराधियों के मन में कानून का भय और आम नागरिकों के मन में पुलिस के प्रति विश्वास बना रहे।

समारोह में विभिन्न विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं—सर्वेश कुमार, किरण, मीताली बुग्गे, देवेन्द्र सिंह, भरत कुमार, जयप्रकाश राठौर, सचिन यादव, सुंदर मनीष, जितेन्द्र कुमार वैष्णव, जितेंद्र सिंह राजपूत एवं राकेश वैष्णव—को ट्रॉफी एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्री मनोज पिंगुआ, एडीजी श्री दीपांशु काबरा, अकादमी के संचालक श्री अजय यादव, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक पल्लव सहित अन्य अधिकारी एवं बड़ी संख्या में प्रशिक्षुओं के परिजन उपस्थित थे।

खैरागढ़ के ईको कैंप छिंदारी में 'बर्डवॉक' बना आकर्षण का केंद्र

वन विभाग खैरागढ़ द्वारा ईको कैंप छिंदारी में शुरू की गई 'बर्डवॉक' पहल प्रकृति प्रेमियों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई है। यह पहल वन मंत्री श्री केदार कश्यप की प्रेरणा और प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) श्री अरुण कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में संचालित की जा रही है। इसका उद्देश्य स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। वर्ष 2026 से प्रारंभ इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को विशेषज्ञों की देखरेख में पक्षी भ्रमण (बर्डवॉक) आयोजित किया जा रहा है। इसमें आम नागरिकों, विद्यार्थियों और प्रकृति प्रेमियों को भाग लेने का अवसर मिल रहा है।

उल्लेखनीय है कि ईको कैंप छिंदारी जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्र है, जहां छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली पक्षियों की लगभग 35 प्रतिशत प्रजातियाँ देखी जा सकती हैं। यहां आने वाले पर्यटक विभिन्न रंग-बिरंगे पक्षियों को नजदीक से देखकर मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। हाल के बर्डवॉक कार्यक्रमों में खैरागढ़ के संगीत एवं कला के छात्र- छात्राओं सहित दुर्ग, रायपुर और राजनांदगांव से आए पर्यटकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतिभागियों को पक्षियों के व्यवहार, घोंसला निर्माण और उनके प्राकृतिक आवास के बारे में जानकारी दी जा रही है। यह पहल केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों को प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनने की सीख भी देती है। भ्रमण के दौरान प्रतिभागियों को शांत रहने, प्लास्टिक का उपयोग न करने और वन्यजीवों के आवास का सम्मान करने जैसे नियमों का पालन कराया जाता है।

पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए वयस्कों से 200 रुपए तथा विद्यार्थियों से 50 रुपए का सहयोग शुल्क निर्धारित किया गया है। ईको कैंप का संचालन स्थानीय समुदाय द्वारा किया जा रहा है, जिसे वन विभाग का वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग प्राप्त है। ईको कैंप छिंदारी में बर्डवॉक के साथ-साथ बोटिंग, टेंटिंग, कैंपिंग तथा छत्तीसगढ़ी पारंपरिक व्यंजनों जैसे फरा, ठेठरी और खुरमी का आनंद लेने की भी सुविधा उपलब्ध है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर यह स्थल पर्यटकों के लिए एक आदर्श पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है।

वन विभाग ने इच्छुक नागरिकों से बर्डवॉक में शामिल होने के लिए अग्रिम पंजीकरण कराने का आग्रह किया है, ताकि सभी को सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण अनुभव मिल सके। यह पहल इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका

छत्तीसगढ़ को बड़ी उपलब्धि

एक साल में 6 लाख आवासों का काम पूरा

छत्तीसगढ़ ने ग्रामीण आवास निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। चालू वित्त वर्ष 2025-26 में छह लाख से अधिक आवास पूर्ण किए हैं। यह इस वर्ष देश में सर्वाधिक है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, प्रधानमंत्री जनमन योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के सशक्त और समन्वित क्रियान्वयन से यह उपलब्धि संभव हो पाई है। जिससे प्रदेश आवास निर्माण के क्षेत्र में एक प्रभावी मॉडल के रूप में उभरा है।

अधिकारियों ने इस बात की जानकारी सोमवार को दी। अधिकारियों ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में 6 लाख से ज्यादा मकान के निर्माण का कार्य पूरा कर लिया है। वहीं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस उपलब्धि पर कहा कि छत्तीसगढ़ ने ग्रामीण आवास निर्माण में एक नया इतिहास रचते हुए 'सबको आवास' के संकल्प को तेजी से साकार किया है।

छत्तीसगढ़ के रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने ग्रामीण आवास निर्माण के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश में 6 लाख से अधिक ग्रामीण आवासों का निर्माण पूर्ण किया गया है, जो इस वर्ष देश में सर्वाधिक है। विभिन्न आवास योजनाओं के समन्वित और प्रभावी क्रियान्वयन से छत्तीसगढ़ एक सफल मॉडल के रूप में उभरकर सामने आया है।

महिला सशक्तिकरण और रोजगार को मिला बढ़ावा

आवास निर्माण के साथ-साथ प्रदेश में महिला सशक्तिकरण और रोजगार सृजन को भी नई गति मिली है। 'डीलर दीदी' मॉडल के तहत 9 हजार से अधिक महिला स्व-सहायता समूह सदस्य निर्माण सामग्री की आपूर्ति कर 'लखपति दीदी' बनी हैं। इसके अलावा हजारों महिला समूहों को आजीविका के अवसर मिले हैं और 6 हजार से अधिक राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें 1200 से ज्यादा 'रानी मिस्त्री' शामिल हैं। आत्मसमर्पित नक्सलियों को भी इस पहल से जोड़कर उन्हें सम्मानजनक रोजगार प्रदान किया गया है।

तेजी, पारदर्शिता और जवाबदेही से छत्तीसगढ़ बना आवास निर्माण का मॉडल

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस उपलब्धि पर कहा कि छत्तीसगढ़ ने ग्रामीण आवास निर्माण में एक नया इतिहास रचते हुए 'सबको आवास' के संकल्प को तेजी से साकार किया है। उन्होंने बताया कि सरकार के प्रथम कैबिनेट निर्णय में 18 लाख आवास स्वीकृत कर इस दिशा में ठोस शुरुआत की गई और वर्तमान में सर्वे सूची में शामिल सभी पात्र हितग्राहियों को कवर कर लिया गया है, जिससे यह सुनिश्चित हुआ है कि कोई भी पात्र परिवार आवास से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 5.87 लाख, प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के अंतर्गत 13 हजार तथा मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 10 हजार से अधिक आवास पूर्ण किए गए हैं।योजनाओं के प्रभावी समन्वय से 6 लाख से अधिक आवासों का लक्ष्य पार किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह उपलब्धि वर्ष 2016 में योजना प्रारंभ होने के बाद प्रदेश में किसी एक वित्तीय वर्ष में सर्वाधिक आवास पूर्ण होने का रिकॉर्ड है, जो तेज क्रियान्वयन और प्रभावी मॉनिटरिंग को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह पहल केवल आवास निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई गति दे रही है। 'डीलर दीदी' मॉडल के तहत 9 हजार से अधिक महिला स्व-सहायता समूह सदस्य आवास निर्माण सामग्री की आपूर्ति कर 'लखपति दीदी' बनकर आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं।

प्रदेश की लाइफलाइन हुई सशक्त

शहर में 15 और गांव में 30 मिनट में पहुंचेगी 108 सेवा

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 370 नई एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी

प्रदेश में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ और प्रभावी बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल की गई। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 300 बेसिक लाइफ सपोर्ट (BLS) एवं 70 एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट (ALS) एम्बुलेंसों को हरी झंडी दिखाकर प्रदेश के सभी जिलों के लिए रवाना किया। इसके साथ ही 108 एम्बुलेंस की समस्त सेवाएं प्रदेशभर में तत्काल प्रभाव से प्रारंभ हो गई हैं, जिससे आपातकालीन परिस्थितियों में नागरिकों को त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सहायता सुनिश्चित होगी।

इस पहल के अंतर्गत पहली बार प्रदेश में 5 नियोनेटल ALS एम्बुलेंसों की शुरुआत की गई है, जो नवजात शिशुओं की आपातकालीन देखभाल के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगी। यह सेवा राज्य की नवजात सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है तथा गंभीर स्थिति में नवजात शिशुओं को सुरक्षित रूप से उच्च स्तरीय उपचार केंद्रों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं निरंतर सुदृढ़ हो रही हैं और पिछले दो वर्षों में इस क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता का भरोसा सरकारी अस्पतालों में लगातार बढ़ा है, जहां उन्हें समय पर उपचार मिल रहा है। उप-स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण एवं उन्नयन के कारण अब लोगों को छोटे-छोटे इलाज के लिए दूर शहरों की ओर नहीं जाना पड़ रहा है।

- 300 BLS, 70 ALS के साथ पहली बार 5 नियोनेटल ALS
- नवजात शिशुओं के लिए 'चलते-फिरते ICU की शुरुआत

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य है कि शहरी क्षेत्रों में 15 मिनट और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 मिनट के भीतर एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराई जाए, ताकि हर जरूरतमंद मरीज तक समय पर स्वास्थ्य सहायता पहुंच सके। उन्होंने कहा कि 108 एम्बुलेंस सेवा का यह विस्तार आम जनता के विश्वास को और सशक्त करेगा कि संकट की घड़ी में सरकार पूरी संवेदनशीलता और तत्परता के साथ उनके साथ खड़ी है।

मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से पहली बार शुरू की गई 5 नियोनेटल ALS एम्बुलेंस सेवा का उल्लेख करते हुए कहा कि यह नवजात शिशुओं के जीवन की सुरक्षा के प्रति सरकार की गंभीरता और प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी

जायसवाल ने अपने संबोधन में कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं के लिहाज से आज का दिन राज्य के लिए ऐतिहासिक है और इससे लाखों लोगों को त्वरित चिकित्सा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य बन गया है, जहां नियोनेटल एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का आभार प्रकट करते हुए ने कहा कि छत्तीसगढ़ अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो रहा है और आने वाले समय में इसमें और तेजी देखने को मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि एम्बुलेंस सेवा में किसी भी प्रकार की देरी या कमी की शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, जिसके लिए विशेष मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किया गया है।

प्रदेश में एम्बुलेंस सेवा की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि शहरी क्षेत्रों में 15 मिनट एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 30 मिनट के भीतर एम्बुलेंस सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि प्रत्येक जरूरतमंद तक समय पर सहायता पहुंच सके।

नियोनेटल एम्बुलेंस सेवा को अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। इनमें प्रशिक्षित नवजात इमरजेंसी तकनीशियन, 24X7 ईएमटी एवं पायलट की उपलब्धता के साथ विशेषज्ञ चिकित्सक का ऑनलाइन मार्गदर्शन सुनिश्चित किया गया है। इन एम्बुलेंसों में इन्क्यूबेटर, वेंटिलेटर, डिफिब्रिलेटर, सिरिंज पंप, नेब्युलाइज़र, सक्शन मशीन, पर्याप्त ऑक्सीजन सपोर्ट एवं 41 प्रकार की आपातकालीन दवाओं सहित सभी आवश्यक जीवनरक्षक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो इन्हें 'चलते-फिरते नवजात आईसीयू' के रूप में स्थापित करती हैं।

इसके अतिरिक्त, BLS एवं ALS एम्बुलेंसों में मरीजों को मौके पर ही प्राथमिक एवं उन्नत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए बीपी मॉनिटर, पल्स ऑक्सीमीटर, ईसीजी मॉनिटर, ग्लूकोमीटर जैसी जांच सुविधाओं के साथ ऑक्सीजन सपोर्ट, नेब्युलाइजेशन एवं अन्य आपातकालीन उपचार व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। गंभीर मरीजों के सुरक्षित स्थानांतरण हेतु पोर्टेबल वेंटिलेटर, डिफिब्रिलेटर मॉनिटर, सिरिंज पंप, लैरिंजोस्कोप सहित अन्य उन्नत उपकरण भी उपलब्ध कराए गए हैं। यह समग्र पहल प्रदेश के शहरी एवं दूरस्थ क्षेत्रों में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभ, त्वरित एवं प्रभावी उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए नागरिकों के लिए एक मजबूत जीवनरक्षक तंत्र के रूप में स्थापित होगी।

इस अवसर पर विधायक श्री मोती लाल साहू, विधायक श्री इंद्र कुमार साहू, सीजीएमएससी के अध्यक्ष श्री दीपक म्हस्के, स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्री अमित कटारिया, संचालक स्वास्थ्य सेवाएं श्री संजीव झा, प्रबंध संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन श्री रणबीर शर्मा, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा श्री रितेश अग्रवाल सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

खुद से सीखने वाले सूरज माशी ने उधार के स्पाइक्स पहन जीता 5000 मीटर का रजत पदक

सूरज नासिक में रहते हैं और ट्रेनिंग का खर्च हर महीने 2-3 दौड़ों में भाग लेकर मिलने वाली इनामी राशि से निकालते हैं

नासिक के एथलेटिक्स ट्रैक पर सूरज माशी और उनके कुछ साथी अक्सर अपने सीनियर खिलाड़ियों को ट्रेनिंग करते हुए बड़े ध्यान से देखते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे सिर्फ देख नहीं रहे होते, बल्कि हर छोटी-बड़ी चीज को समझकर उसे अपनी ट्रेनिंग में लागू करने की कोशिश करते हैं। सूरज उन आदिवासी खिलाड़ियों के समूह का हिस्सा हैं, जो हर महीने कोच की फीस नहीं दे सकते और अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए जो भी मदद मिलती है, उसी पर निर्भर रहते हैं। दौड़ना ही उनका सबसे बड़ा हुनर है, जिसने उन्हें यहां तक पहुंचाया है और जो एक दिन उनकी जिंदगी बदल सकता है।

सूरज ने कहा, कोचिंग फीस 4000 रुपये प्रति माह है, जिसे मैं वहन नहीं कर सकता। मैं नासिक में किराये पर रहकर पढ़ाई करता हूं और किराया मुझे महाराष्ट्र और गुजरात में दौड़ों में भाग लेकर मिलने वाली इनामी राशि से ही देना पड़ता है। इसलिए मैं खुद ही ट्रेनिंग करता हूं और जब कहीं अटकता हूं तो सीनियर्स या ट्राइबल विभाग के कोच से सलाह लेता हूं। यही सूरज खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुष 5000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने में सफल रहे।

सूरज हर महीने सिर्फ 300 रुपये देकर ट्रेनिंग सुविधा का उपयोग करते हैं और सेकेंड हैंड जूते और स्पाइक्स में अभ्यास करते हैं। उनके स्पाइक्स काफी घिस चुके थे, इसलिए उन्हें इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए एक साथी धावक से स्पाइक्स उधार लेने पड़े। पालघर जिले के मोखाडा तालुका के एक छोटे से गांव से आने वाले सूरज की जिंदगी संघर्ष और आत्मनिर्भरता की कहानी है। वारली जनजाति से ताल्लुक रखने वाले सूरज, जो एक दिहाड़ी मजदूर के बेटे हैं और चार बहनों के बाद पैदा हुए पहले बेटे हैं, बचपन से ही आत्मनिर्भर रहे हैं। सरकारी आश्रम शाला में पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने दौड़ना शुरू किया।

स्कूल के एक खेल आयोजन के दौरान उन्हें दौड़ने का शौक लगा और तब से यह उनके जीवन का सहारा बन गया। जब सूरज 10वीं कक्षा में थे, उनकी मां घर में गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गईं और अब चल-फिर नहीं पातीं। पिछले साल उनकी एक बड़ी बहन का निधन हो गया और उनके तीन छोटे भाई उनसे मार्गदर्शन और सहारे की उम्मीद रखते हैं। स्कूल पूरा करने के बाद सूरज पढ़ाई और खेल को आगे बढ़ाने के लिए नासिक चले गए, लेकिन शहर में रहना और परिवार का सहारा बनना उनके लिए लगातार चुनौती बना हुआ है। उन्होंने कहा, मैं स्थानीय प्रतियोगिताओं और क्रॉस-कंट्री दौड़ों में भाग लेकर हर महीने करीब 3000 से 5000 रुपये कमा लेता हूं। उसी में से कुछ पैसे बचाकर मैं अपने पिता को भेजता हूं और अपनी पढ़ाई, ट्रेनिंग और बाकी जरूरतें पूरी करता हूं।

इस साल जून में 19 साल के होने वाले सूरज ने 18 साल की उम्र के बाद पुलिस विभाग में नौकरी पाने की भी कोशिश की। उन्होंने ज्यादातर शारीरिक परीक्षण पास कर लिए, लेकिन शॉट पुट में निर्धारित दूरी पूरी नहीं कर पाने के कारण चयन से चूक गए। हालांकि नौकरी पाना अभी भी उनकी प्राथमिकता है, लेकिन सूरज को भरोसा है कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में उनके प्रदर्शन से उनकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आएगा। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र सरकार खेलो इंडिया गेम्स के पदक विजेताओं को नकद पुरस्कार भी देती है।

पहलवान पूनम ने करियर खत्म कर देने वाली चोट से पार पाते हुए 9 साल के खिताबी सूखे को किया समाप्त

कुश्ती जैसे खेल में जहां फिटनेस और ताकत सबसे बड़ी जरूरत होती है, वहां चोटिल कंधे के साथ मैट पर उतरना अपने आप में बड़ा जोखिम है। लेकिन झारखंड की 19 वर्षीय पहलवान पूनम ऑरन ने इस जोखिम को चुनौती में बदला और दर्द के बावजूद मुकाबले दर मुकाबले जीत हासिल करते हुए पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया।

फाइनल में भी पूनम बाएं कंधे पर पट्टी बांधकर उतरीं। हर मूव के साथ दर्द साफ नजर आ रहा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अंत तक लड़ते हुए मुकाबला अपने पक्ष में किया। पूनम ने महिलाओं की 50 किग्रा वर्ग के फाइनल में तेलंगाना की के. गीता को हराकर स्वर्ण पदक जीता। अपने करियर का पहला स्वर्ण पदक जीतने के बाद पूनम ने साई मीडिया से कहा, हार कैसे मान लेती सर? जब नौ साल से हार नहीं मानी, तो अब कैसे मान लेती। मेरी यह चोट बहुत पुरानी है। छह साल पहले मेरा कंधा उतर गया था। बीच में ठीक हुआ, लेकिन फिर ट्रेनिंग के दौरान दोबारा चोट लग गई। इसके बावजूद मैंने वापसी की और अब मैंने यहां पर गोल्ड जीता है।उन्होंने कहा, अपने करियर की शुरुआत से ही मैं चोटों से जूझ रही हूँ, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। गोल्ड मेडल जीतना किसी सपने के सच होने जैसा लगता है। नौ साल तक गोल्ड न जीत पाने के दर्द के मुकाबले यह चोट कुछ भी नहीं है। झारखंड के चतरा जिले के सुइयाबार गांव की रहने वाली पूनम के लिए यह जीत किसी सपने के सच होने जैसी है। साल 2017 में जब उन्होंने कुश्ती की शुरुआत की थी, उसी दौरान एक गंभीर चोट ने उन्हें करीब एक साल तक मैट से दूर कर दिया।

आईएएस रजत बंसल बने जनसंपर्क आयुक्त, सीएम सचिवालय में विशेष सचिव की भी जिम्मेदारी,

आईएएस अफसर रजत कुमार को सरकार ने न केवल जनसंपर्क आयुक्त बनाया है बल्कि स्पेशल सिकरेट्री टू सीएम से लेकर उनका डायरेक्टर माईनिंग और एमडी माईनिंग कारपोरेशन भी यथावत रहेगा। एन बैजेंद्र कुमार को छोड़ किसी भी जनसंपर्क आयुक्त का इतना बड़ा पोर्टफोलियो नहीं रहा।

रायपुर। कई दिनों की अटकलबाजियों और चर्चाओं पर विराम लगाते हुए छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने रजत बंसल को नया जनसंपर्क आयुक्त अपाइंट कर दिया। इसके साथ ही वर्तमान जनसंपर्क आयुक्त डॉ0 रवि मित्तल को पीएमओ के लिए आज कार्यमुक्त कर दिया।

रजत बंसल 2012 बैच के आईएएस हैं। छत्तीसगढ़ कैडर में वे बैचवाइज सबसे सीनियर हैं। रजत संवाद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी भी होंगे। सीपीआर और संवाद के सीईओ के साथ उन्हें स्पेशल सिकरेट्री टू सीएम सचिवालय भी बनाया गया है। इसके अलावा उनके पास डायरेक्टर माईनिंग और एमडी माईनिंग कारपोरेशन का भीप अतिरिक्त दायित्व होगा।

सरकार ने जताया भरोसा

नए जनसंपर्क आयुक्त के लिए सरकार के समक्ष तीन-चार नाम थे। मगर आखिरकार रजत बंसल के नाम पर न केवल मुहर लगाया गया बल्कि उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें सीएम सचिवालय में पोस्टिंग दी गई। इसके अलावा उनके पास डायरेक्टर माईनिंग और एमडी माईनिंग कारपोरेशन का भी प्रभार रहेगा। छत्तीसगढ़ में बैजेंद्र कुमार को छोड़ दें तो किसी जनसंपर्क आयुक्त के पास इतना चार्ज नहीं रहा। इस तरह कह सकते हैं कि सरकार ने रजत बंसल पर भरोसा जताया है।

जनसंपर्क आयुक्त के लिए वैसे तो पब्लिक डोमेन से लेकर ब्यूरोक्रेसी के गलियारों में कई नाम चल रहे थे। मगर रजत बंसल को सबसे उपयुक्त समझा गया। रजत बंसल की खासियत यह है कि वे काफी मिलनसार तो हैं ही, रिजल्ट ओरियेंटेड काम करते हैं। माईनिंग में उन्होंने कम समय में काफी काम किया। इसके अलावे उनकी सबसे बड़ी खासियत लो प्रोफाइल में रहना है। वे पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के दामाद हैं। राजीव कुमार जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, तब भी वे लाइमलाइट से दूर लो प्रोफाइल में बने रहे। रजत काफी विनम्र स्वभाव के आईएएस माने जाते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के भी वे प्रिय हैं। सारी खूबियों को देखते हुए रजत को सरकार की छबि चमकाने वाले विभाग का दायित्व सौंपा गया है।

3 महीने में 300 करोड़ का राजस्व

रजत बंसल मुख्यमंत्री से लेकर हाई अथॉरिटी की नजर में इसलिए आए कि उन्होंने माईनिंग में आते ही इतने बड़े-बड़े काम किए, वैसा आज तक नहीं हुआ। माईनिंग में उनके द्वारा किए गए रिफार्म की वजह से सरकार को पिछले तीन महीने में 300 करोड़ का राजस्व बढ़ गया। माईनिंग में वे ऐसा काम कर रहे कि दलालों और माफियाओं की दाल नहीं गल पाएगी। वे ड्रोन सिस्टम से खनन एरिया की निगरानी कराने जा रहे हैं। ड्रोन का कंट्रोल रायपुर में रहेगा। रायपुर में बैठेक-बैठे पता चल जाएगा कि कहां से कितनी रेत या खनिज को पार किया जा रहा या माइनिंग कंपनियां वास्तविक जगह पर खनन कर रही या रकबा बढ़ाकर माईनिंग कर ले रही।

जानिए रजत बंसल के बारे में

रजत बंसल छत्तीसगढ़ कैडर के 2012 बैच के आईएएस अफसर हैं। वे हरियाणा के रहने वाले हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी की है। अपने पहले प्रयास में आईपीएस बने फिर दूसरे प्रयास में आईएएस।

छत्तीसगढ़ कैडर के 2012 बैच के आईएएस रजत बंसल हरियाणा के रहने वाले है। उनके पिता भारतीय वन सेवा के अधिकारी थे। वे यूपी कैडर के आईएफएस अधिकारी रहे इसलिए रजत की शुरूआती स्कूली शिक्षा यूपी में हुई। रजत बंसल का जन्म 25 जुलाई 1988 को हुआ है। उनकी स्कूली शिक्षा लॉ मार्टिनियर स्कूल लखनऊ व डीपीएस स्कूल आरके पुरम दिल्ली से हुई है। दसवीं में रजत बंसल ने स्कूल में टॉप किया था। बीट्स प्लानी से कंप्यूटर साइंस ब्रांच से इंजीनियरिंग किया। पढ़ाई के दौरान फ्रांस में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल हुए। जिसमे उन्हें स्कॉलरशिप मिली।

यूपीएससी में सलेक्शन

2009 से अप्रेल 2011 तक इंफोसिस कंपनी पुणे में जूनियर रिसर्च एसोसिएट के तौर पर कार्यरत रहें। इस दौरान यूपीएससी की तैयारी भी करते रहे। हफ्ते में दो दिन नौकरी करते हुए रजत बंसल कोचिंग करते थे। पहले प्रयास में 168 रैंक लाकर यूपीएससी क्रैक करते हुए उनका चयन आईपीएस के लिए हुआ। रजत बंसल को पश्चिम बंगाल कैडर मिला। 9 माह तक रजत बंसल ने आईपीएस की ट्रेनिंग की। दूसरे प्रयास में रजत बंसल का रैंक 85 वां आया और वे आईएएस के लिए चुने गए।

प्रोफेशनल कैरियर

रजत बंसल ने 3 सितंबर 2012 को आईएएस की सर्विस ज्वाइन की। रजत बंसल की फील्ड ट्रेनिंग के लिए पहली पोस्टिंग सहायक कलेक्टर के रूप में रायगढ़ जिले में मिली। अगस्त 2014 में राजनांदगांव के एसडीएम बने। राजनांदगांव के सीईओ जिला पंचायत बने। फिर सूरजपुर जिले में जिला पंचायत सीईओ बने। रायपुर नगर निगम के कमिश्नर रहें।

रजत बंसल धमतरी, बस्तर व बलौदाबाजार जिलों के कलेक्टर रहें। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के आयुक्त रहें। वर्तमान में वे डायरेक्टर माईनिंग, एमडी माईनिंग कारपोरेशन और स्पेशल सिकरेट्री गुड गवर्नेंस हैं। मगर अब उन्हें जनसंपर्क आयुक्त के साथ विशेष सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय बनाया गया है। माईनिंग के उनके दोनों प्रभार यथावत रहेंगे। सिर्फ स्पेशल सिकरेट्री गुड गवर्नेंस हटेगा।

आर्थिक संबल से आत्मविश्वास तक, सशक्त हो रही छत्तीसगढ़ की महिलाएं

महतारी वंदन योजना केवल हर माह मिलने वाली 1000 रुपये की आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह महिलाओं के सपनों को पंख देने, उनके आत्मसम्मान को मजबूत करने और परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का सशक्त माध्यम बन गई है।

किसी भी समाज की वास्तविक प्रगति तब मानी जाती है जब उसकी महिलाएं सशक्त, आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जीने लगें। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना इसी दिशा में एक ऐतिहासिक और संवेदनशील पहल बनकर उभरी है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के मार्गदर्शन में यह योजना आज लाखों महिलाओं के जीवन में आत्मविश्वास, आर्थिक संबल और नई उम्मीदों का संचार कर रही है।

महतारी वंदन योजना केवल हर माह मिलने वाली 1000 रुपये की आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह महिलाओं के सपनों को पंख देने, उनके आत्मसम्मान को मजबूत करने और परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का सशक्त माध्यम बन गई है। प्रदेश के गांव-गांव से ऐसी प्रेरक कहानियां सामने आ रही हैं, जो बताती हैं कि छोटे-छोटे आर्थिक सहयोग से भी बड़े सामाजिक बदलाव संभव हैं।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बस्तर में आयोजित वृहद महतारी वंदन कार्यक्रम के दौरान कई महिलाओं ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से वर्चुअल संवाद कर अपने जीवन में आए बदलाव साझा किए। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के ग्राम खोडरी की श्रीमती अनीता साहू ने बताया कि पहले आर्थिक कठिनाइयों के कारण परिवार चलाना मुश्किल था, लेकिन योजना से मिली राशि से उन्होंने सिलाई मशीन खरीदी और अनीता सिलाई सेंटर शुरू किया। आज वे सिलाई, खेती और मजदूरी के माध्यम से अपने परिवार को बेहतर जीवन दे रही हैं। उनका यह सफर संघर्ष से आत्मनिर्भरता तक की प्रेरक कहानी बन गया है।

मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले की श्रीमती मिथलेश चतुर्वेदी ने भी अपने जीवन का भावुक अनुभव साझा किया। पति के निधन के बाद परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी। ऐसे कठिन समय में महतारी वंदन योजना ने उन्हें आर्थिक संबल दिया और उन्होंने ई-रिक्शा खरीदकर आजीविका का नया रास्ता चुना। आज वे आत्मसम्मान के साथ अपने परिवार का पालन-पोषण कर रही हैं और समाज में आत्मनिर्भर महिला की पहचान बना चुकी हैं।

कोरिया जिले की ग्राम डुमरिया निवासी श्रीमती बाबी राजवाड़े बताती हैं कि खेती-किसानी में मिलने वाली मासिक राशि उनके लिए बड़ी मदद साबित हो रही है। बीज, खाद और अन्य कृषि जरूरतों को पूरा करना अब पहले की तुलना में आसान हो गया है। वहीं ग्राम आमापारा की श्रीमती सुंदरी पैकरा इस राशि का उपयोग अपने बच्चों की पढ़ाई में कर रही हैं, जिससे उनके बच्चों के भविष्य को नई दिशा मिल रही है।

भरतपुर विकासखंड के ग्राम चांटी की श्रीमती सविता सिंह की कहानी इस योजना की सार्थकता को और मजबूत करती है। उन्होंने महतारी वंदन योजना की राशि को बचाकर सिलाई मशीन खरीदी और सिलाई कार्य शुरू किया। आज वे गांव में कपड़ों की सिलाई कर नियमित आय अर्जित कर रही हैं और अपने बच्चों की पढ़ाई-लिखाई का खर्च स्वयं उठा रही हैं। उनकी सफलता ने गांव की अन्य महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी है।

महतारी वंदन योजना का व्यापक प्रभाव प्रदेश के हर जिले में दिखाई दे रहा है। लगभग 69 लाख विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये की सहायता सीधे उनके बैंक खातों में दी जा रही है और अब तक 25 किस्तों के माध्यम से 16 हजार 237 करोड़ रुपये से अधिक की राशि डीबीटी के जरिए प्रदान की जा चुकी है। यह नियमित आर्थिक सहयोग महिलाओं के जीवन में स्थिरता और आत्मविश्वास ला रहा है। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह महिलाओं को केवल सहायता नहीं देती, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देती है। महिलाएं इस राशि से छोटे-छोटे व्यवसाय शुरू कर रही हैं, बच्चों की पढ़ाई में निवेश कर रही हैं, खेती-किसानी को मजबूत बना रही हैं और परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। इससे परिवार, समाज और राज्य—तीनों स्तरों पर सकारात्मक बदलाव दिखाई दे रहा है।

महिलाओं का कहना है कि पहले छोटी-छोटी जरूरतों के लिए भी उन्हें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब महतारी वंदन योजना ने उन्हें आत्मसम्मान के साथ जीने की ताकत दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना उनके जीवन में नई उम्मीद और नया आत्मविश्वास लेकर आई है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बंद पड़े 123 स्कूल फिर से गुलज़ार

इन क्षेत्रों में बंदूक की गूंज की जगह स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई और किताबों की सरसराहट दे रही है सुनाई

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा की नई अलख, सरकार और सुरक्षाबलों की पहल से जगी है, दुर्गम इलाकों में मॉडल स्कूल, %नियद नेल्ला नार% जैसी योजनाओं और समर्पित शिक्षकों के माध्यम से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है, जो अब फर्राटेदार अंग्रेजी बोलकर और तकनीकी कौशल सीखकर अपना भविष्य संवार रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुदूर क्षेत्रों में अब शिक्षा का उजाला फिर से फैलने लगा है। शासन के सतत प्रयासों और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में चल रही योजनाओं के कारण सुकमा जिले में बंद पड़े स्कूलों को पुनः संचालित किया गया है, जिससे शिक्षा व्यवस्था को नई मजबूती मिली है। अब इन क्षेत्रों में बंदूक की गूंज की जगह स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई, ककहरा और किताबों की सरसराहट सुनाई दे रही है, जो एक उज्ज्वल और सुरक्षित भविष्य का संकेत है।

पुनर्जीवित हुई शिक्षा व्यवस्था

वर्ष 2006 में माओवादी प्रभाव और सलवा जुडूम आंदोलन के चलते सुकमा जिले के कुल 123 स्कूल बंद हो गए थे, जिनमें 101 प्राथमिक और 21 माध्यमिक विद्यालय शामिल थे। प्रशासन के लगातार प्रयासों से अब इन सभी स्कूलों को पुनः प्रारंभ कर दिया गया है। वर्तमान में जिले में एक भी ऐसा विद्यालय नहीं है जो नक्सल प्रभाव के कारण बंद हो। नक्सल आतंक से कभी छूटा था स्कूल, अब सुशासन से फिर जागी शिक्षा की अलख,उम्मीदों को मिल रहा सहारा। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भय के कारण बंद हुए स्कूल फिर से खुल रहे हैं। स्कूल छोड़ चुके बच्चों की स्कूल में वापसी हो रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में शिक्षा का उजियारा बस्तर क्षेत्र की हर दिशा में फैल रहा है।

बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय सुधार

शिक्षा के विस्तार और छात्रों के बेहतर भविष्य को ध्यान में रखते हुए जिले में बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ किया गया है। वर्तमान में 16 पोटा केबिन (आवासीय विद्यालय) संचालित हैं, जिनमें 6,722 छात्र अध्ययनरत हैं। इसके साथ ही 16 पोटा केबिन छात्रावासों में 1,389 विद्यार्थी रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय टाइप-3 (कक्षा 6वीं से 12वीं) के 3 विद्यालयों में 600 छात्राएं तथा टाइप-4 (कक्षा 9वीं से 12वीं) के 2 छात्रावासों में 200 छात्राएं लाभान्वित हो रही हैं।

नियद नेल्ला नार योजना से नई शुरुआत

वर्ष 2024-25 में नियद नेल्ला नार योजना के अंतर्गत सुकमा जिले के चयनित गांवों में 07 नए प्राथमिक विद्यालय खोले गए हैं, जिनमें अब तक 210 बच्चों ने प्रवेश लिया है। भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए प्रशासन द्वारा 19 और नए विद्यालय खोलने का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिससे शिक्षा का दायरा और अधिक विस्तृत होगा।

बदलाव की नई कहानी

जमीनी स्तर पर हो रहे ये सकारात्मक बदलाव न केवल बच्चों के भविष्य को संवार रहे हैं, बल्कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विश्वास और विकास की नई नींव भी रख रहे हैं। शासन द्वारा 'पहले' और 'अब' की तस्वीरों के माध्यम से इस परिवर्तन को प्रमाणित किया गया है।

केआईटीजी उद्घाटन पर बोलीं मीराबाई चानू

एशियन गेम्स का पदक जीतना मेरा अधूरा सपना

टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू ने खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स को बताया गेम-चेंजर

कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स के चलते वेट कैटेगरी बदलना बड़ी चुनौती

टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू ने खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स को बताया गेम-चेंजरटोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता सेखोम मीराबाई चानू ने खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के उद्घाटन अवसर पर अपने करियर के सबसे बड़े अधूरे लक्ष्य, एशियन गेम्स पदक का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह सपना अब भी उनके लिए सर्वोच्च्च प्राथमिकता है। पिछले एक दशक से भारतीय वेटलिफ्टिंग की अग्रणी खिलाड़ी रही मीराबाई ने ओलंपिक, विश्व चैंपियनशिप और कॉमनवेल्थ गेम्स में कई पदक जीते हैं, लेकिन एशियाई खेलों में पदक अब तक उनसे दूर रहा है। उन्होंने 2014 इंचियोन एशियन गेम्स में 19 वर्ष की उम्र में पदार्पण किया था, जहां वे नौवें स्थान पर रहीं। इसके बाद 2018 जकार्ता एशियन गेम्स में पीठ की चोट के कारण हिस्सा नहीं ले सकीं, जबकि 2022 हांगझोउ एशियन गेम्स में हिप की चोट ने उनका सपना अधूरा छोड़ दिया।

31 वर्षीय मीराबाई ने कहा कि -एशियन गेम्स मेरे लिए बेहद खास है। वहां प्रतियोगिता का स्तर बहुत ऊंचा होता है, और यही इसे सबसे चुनौतीपूर्ण बनाता है। मेरा सपना है कि मैं वहां पदक जीतूं। हालांकि, इस लक्ष्य की राह आसान नहीं है। नियमों में बदलाव के कारण उन्हें 48 किलोग्राम और 49 किलोग्राम वर्ग के बीच संतुलन बनाना होगा। वे 23 जुलाई से 2 अगस्त तक ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में 48 किलोग्राम वर्ग में उतरेंगी, जबकि 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक नागोया (जापान) में आयोजित एशियन गेम्स में 49 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा करेंगी।

उन्होंने बताया कि कॉमनवेल्थ गेम्स तक मैं 48 किलोग्राम में खेलूंगी, लेकिन एशियन गेम्स के लिए फिर से 49 किलोग्राम वर्ग में आना होगा, जो एक बड़ी चुनौती है। मीराबाई ने हाल ही में राष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 48 किलोग्राम वर्ग में तीन नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए। उन्होंने स्नैच में 89 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 116 किलोग्राम वजन उठाते हुए कुल 205 किलोग्राम के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया, जो उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।

इस अवसर पर उन्होंने खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की सराहना करते हुए कहा कि यह आयोजन देश के दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों के खिलाड़ियों के लिए बड़ा मंच साबित होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे आने का मौका मिलता है, खासकर उत्तर-पूर्व और जनजातीय इलाकों में जहां बहुत टैलेंट है, लेकिन मंच की कमी रहती है।

मीराबाई ने नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (NCOE), खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और साई ट्रेनिंग सेंटर की भी प्रशंसा की। उनके अनुसार, इन संस्थानों में खिलाड़ियों को उच्चस्तरीय प्रशिक्षण, पोषण और सुविधाएं मिल रही हैं, जो भारतीय खेलों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

धर्म और जाति को लेकर आए 'सुप्रीम आदेश' के राजनीतिक-सामाजिक मायने

कमलेश पांडे

कांग्रेस व समाजवादी मूल की क्षेत्रीय पार्टियां यदि चाहें तो इस मुद्दे पर अपनी राजनीति भी शुरू कर सकती है कि जब हिन्दू, बौद्ध या सिख बनेंगे तो उनका एससी/ओबीसी स्टेटस बरकरार रहेगा, लेकिन जैन, ईसाई, मुसलमान, पारसी आदि बनने पर नहीं, यह कौन सा खिचड़ी न्यायिक दर्शन हैं, जो हर गतिरोध के बाद एक नया गतिरोध पैदा कर देता है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई व्यक्ति हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म से बाहर जाकर धर्म परिवर्तन करता है, तो उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता। दरअसल, आंध्र प्रदेश के एक धर्मांतरित ईसाई पादरी से जुड़े मामले में आए इस नवीनतम फैसले के व्यापक राजनीतिक और सामाजिक मायने हैं। इससे हिन्दू समुदाय के दलितों और पिछड़ों को निशाना बनाकर धर्मांतरित करवाये जाने का पूरा खेल ही अब हतोत्साहित हो जाएगा।

हालांकि, कांग्रेस व समाजवादी मूल की क्षेत्रीय पार्टियां यदि चाहें तो इस मुद्दे पर अपनी राजनीति भी शुरू कर सकती है कि जब हिन्दू, बौद्ध या सिख बनेंगे तो उनका एससी/ओबीसी स्टेटस बरकरार रहेगा, लेकिन जैन, ईसाई, मुसलमान, पारसी आदि बनने पर नहीं, यह कौन सा खिचड़ी न्यायिक दर्शन हैं, जो हर गतिरोध के बाद एक नया गतिरोध पैदा कर देता है। कहने का तातपर्य यह कि ज्यूडिशियल एंटीबायोटिक पॉवर बढ़ाये बिना सम्बन्धित व्यक्ति या समूह का कल्याण नहीं होने वाला है।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गत 23-24 मार्च 2026 को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म (जैसे ईसाई, इस्लाम आदि) में परिवर्तन करने पर अनुसूचित जाति (एससी) का दर्जा तुरंत समाप्त हो जाता है। इस आदेश से एससी/एसटी आरक्षण लाभ और अत्याचार निवारण अधिनियम का संरक्षण खत्म हो जाता है। दरअसल, यह फैसला आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मई 2025 के आदेश पर आधारित है, जहां एक ईसाई पादरी को एससी/एसटी एक्ट के तहत संरक्षण से वंचित किया गया। क्योंकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुसूचित जाति आदेश 1950 के अनुसार केवल निर्दिष्ट धर्मों के अनुयायी ही एससी लाभ ले सकते हैं। ईसाई या इस्लाम अपनाने पर जातिगत पहचान और लाभ दोनों समाप्त हो जाते हैं।

इस फैसले के अहम राजनीतिक मायने हैं। यह फैसला धर्मांतरण पर आधारित आरक्षण दावों को रोक सकता है, जो दक्षिणपंथी दलों के लिए समर्थन बढ़ाएगा। वहीं, अल्पसंख्यक आरक्षण बहस (जैसे दलित ईसाई/मुस्लिम) को प्रभावित कर चुनावी राजनीति में हिंदू एकता पर जोर देगा। राज्य सरकारें ओबीसी/एससी सूचियों की समीक्षा के दबाव में आ सकती हैं। वहीं, इस फैसले के बाद धर्म परिवर्तन और आरक्षण से जुड़ी बहस जोर पकड़ सकती है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आलोक में फैसला दिया है, लेकिन कुछ मसले ऐसे होते है जहां कानून और जमीनी हकीकत आमने-सामने आ जाते हैं। भारत में जाति एक सच्चाई है, जिसे नहीं बदला जा सकता, लेकिन इससे जुड़ी बुराइयों को खत्म करने की तमाम कोशिश होनी चाहिए। जो राजनीतिक और न्यायिक अदूरदर्शिता वश नहीं हो पा रही है और तरह तरह के संवैधानिक विवाद जन्म ले रहे हैं, जिससे राष्ट्रीय हितों को लगातार धक्का लग रहा है।

जहां तक इस फैसले के सामाजिक प्रभाव की बात है तो धर्म परिवर्तन के बाद एससी/ओबीसी का लाभ न मिलने से सामाजिक न्याय की नीति मजबूत होगी, लेकिन धार्मिक रूपांतरण रोकने या जातिगत अस्मिता पर बहस तेज हो सकती है। चूंकि दलित समुदायों में हिंदू/सिख/बौद्ध रहने का दबाव बढ़ेगा, जबकि ईसाई/मुस्लिम समुदायों में असंतोष उत्पन्न हो सकता है। फिर भी कुल मिलाकर देखा जाए तो यह आरक्षण को ऐतिहासिक अन्याय सुधार तक सीमित रखने की दिशा में उठाया गया निर्णायक कदम है। इस पर मौजूदा मोदी सरकार के वैचारिक असर से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह सरकार दलित/ओबीसी हिंदुओं की एकजुटता व समग्र उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है।

हालांकि देश में जाति से जुड़ा सवाल बहुत टेढ़ा और जटिल है। क्योंकि सामाजिक स्तर पर हमेशा से यह बहस का विषय रहा है कि क्या धर्म बदलने भर से जातिगत भेदभाव खत्म हो जाता है? गाहे बगाहे ऐसे मामले सामने आते रहे है, जिनमें दलित या ओबीसी समुदाय के लोगों को दूसरा धर्म अपनाने के बाद भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। पिछले साल मार्च में ही तमिलनाडु के कुछ ईसाई परिवारों, जो पहले दलित थे, ने आरोप लगाया था कि उनके साथ समान व्यवहार नहीं होता। यहां तक कि कब्रिस्तान में उनके लोगों के शवों को दफनाने के लिए भी अलग जगह है।

उल्लेखनीय है कि शीर्ष अदालत के फैसले का आधार संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 है। जिसका क्लॉज 3 कहता है कि हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म को मानने वाले ही एससी श्रेणी में आ सकते है। धर्म परिवर्तन और जाति से जुड़ी यह बहस बहुत पुरानी है। इसके दो पहलू है। एक, जिन धर्मों में जाति व्यवस्था नही है, उन्हें अपनाकर फिर जाति से जुड़े लाभ कैसे लिए जा सकते है। पिछले साल दिसंबर में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया था कि जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया है, उन्होंने अनुसूचित जाति से जुड़े लाभ छोड़ दिए हों।

तब हाईकोर्ट ने कहा था कि धर्म परिवर्तन के बाद भी अनुसूचित जाति समुदाय को मिलने वाले फायदे लेते रहना संविधान के साथ धोखा है। राष्टीय अनुसूचित जाति आयोग के पास इस तरह की कई शिकायतें है और उसने पिछले साल देशभर में जांच भी शुरू की थी। कुल मिलाकर उद्देश्य यह है कि संविधान के तहत मिले अधिकार का दुरुपयोग न होने पाए। क्योंकि जाति और धर्म का दुरुपयोग होने की चिंता शुरू से ही न्यायिक विमर्श का मुद्दा बनी हुई है। लिहाजा ब्रेक के बाद न्यायदेश मिलते रहते हैं।

इंद्रा साहनी केस (1992) से इस फैसले का सम्बन्ध

इंद्रा साहनी केस (1992) मुख्य रूप से ओबीसी आरक्षण पर केंद्रित था, लेकिन हालिया सुप्रीम कोर्ट फैसले (धर्म परिवर्तन पर स्ष्ट दर्जा समाप्ति) से इसका अप्रत्यक्ष संबंध है। दोनों आरक्षण को जाति-आधारित ऐतिहासिक अन्याय सुधार तक सीमित रखने के सिद्धांत साझा करते हैं। इंद्रा साहनी का सार इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी को 27त्न आरक्षण मान्य किया, लेकिन 50त्न कुल सीमा तय की और स्पष्ट किया कि आरक्षण का आधार धर्म या जाति अकेला नहीं हो सकता। क्रीमी लेयर बहिष्कार और पिछड़ापन के सामाजिक-शैक्षिक मापदंड निर्धारित किए गए।

अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय रिपोर्ट

देश में पच्चीस साल से कम उम्र के करीब 40% ग्रेजुएट बेरोज़गार

अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, शिक्षा में पिछले चार दशकों में तेज़ी से वृद्धि के बावजूद 15 से 25 वर्ष आयु वर्ग में बेरोजगारी लगभग 40% और 25 से 29 वर्ष के लोगों में करीब 20% है.

'स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2026' शीर्षक रिपोर्ट में शिक्षा और रोजगार सृजन के बीच बढ़ती खाई को रेखांकित किया गया है. भारत की 15 से 29 वर्ष आयु की युवा आबादी 36.7 करोड़ है, जो कार्यशील आयु वर्ग का लगभग एक-तिहाई हिस्सा है.

रिपोर्ट के अनुसार, इस समूह के 26.3 करोड़ लोग शिक्षा में नहीं हैं और संभावित कार्यबल का हिस्सा हैं. 28 वर्ष की औसत आयु के साथ भारत दुनिया की सबसे युवा अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, लेकिन यह जनसांख्यिकीय लाभ 2030 के बाद कम होने लगेगा, जिससे आने वाले दशक में रोजगार सृजन की गति बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है.

रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में 20 से 29 वर्ष आयु वर्ग के 6.3 करोड़ स्नातकों (ग्रेजुएट) में से 1.1 करोड़ बेरोजगार थे. 15 से 25 वर्ष आयु वर्ग में बेरोजगारी लगभग 40% और 25 से 29 वर्ष के बीच करीब 20% है. जहां 50% युवा पुरुष स्नातक के बाद बेरोजगार दर्ज होने के एक साल के भीतर नौकरी पा लेते हैं, वहीं केवल 7% को स्थायी वेतनभोगी नौकरी मिलती है.

रिपोर्ट यह भी बताती है कि 1983 से स्नातकों में बेरोजगारी दर लगभग 35% से 40% के बीच स्थिर बनी हुई है. पिछले चार दशकों में शिक्षा में नामांकन की तेज़ वृद्धि हुई है, जिससे भारत का उच्च शिक्षा नामांकन दर (28%) समान प्रति व्यक्ति आय वाले देशों के बराबर पहुंच गया है.

युवा महिलाओं में नामांकन 1983 में 38% से बढ़कर 2023 में 68% हो गया, जबकि पुरुषों में यह 49% से बढ़कर 73% हुआ. अनुसूचित जाति (एससी) का नामांकन 2011 से 2023 के बीच 11% से बढ़कर 26% और अनुसूचित जनजाति (एसटी) का 8% से बढ़कर 21% हुआ, हालांकि ये दोनों अभी भी राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं.

हालांकि, रिपोर्ट में पुरुषों के नामांकन में हालिया गिरावट का भी उल्लेख है. शिक्षा में युवा पुरुषों की हिस्सेदारी 2017 में 38% से घटकर 2024 के अंत तक 34% रह गई. आंकड़ों के अनुसार, 72% युवाओं ने परिवार की आय में योगदान देने की जरूरत के कारण पढ़ाई छोड़ दी.

यह शैक्षिक विस्तार बड़े पैमाने पर निजी संस्थानों की वृद्धि से प्रेरित है. उदारीकरण के बाद उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या 1,644 से बढ़कर 69,534 हो गई. कॉलेजों की उपलब्धता 2010 में प्रति लाख युवाओं पर 29 से बढ़कर 2021 में 45 हो गई.

हालांकि, रिपोर्ट में शिक्षकों की भारी कमी की ओर भी ध्यान दिलाया गया है. जहां एआईसीटीई के मानक के अनुसार, एक शिक्षक पर 15 से 20 छात्र होने चाहिए, वहीं निजी कॉलेजों में औसतन 28 और सरकारी कॉलेजों में 47 छात्र प्रति शिक्षक हैं.

व्यावसायिक प्रशिक्षण का भी इसी तरह विस्तार हुआ है. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) की संख्या 2005 में 3,674 से बढ़कर 2025 तक 14,582 हो गई, जिसमें 80% निजी क्षेत्र के हैं. रिपोर्ट के अनुसार, इस विस्तार की कीमत संस्थानों की गुणवत्ता में गिरावट के रूप में चुकानी पड़ी है, नए व निजी आईटीआई गुणवत्ता के मानकों पर पीछे हैं तथा विनिर्माण क्षेत्र से उनका संबंध कमजोर है. हालांकि उच्च शिक्षा का दायरा बढ़ा है, साल 2007 में सबसे गरीब परिवारों के छात्रों की हिस्सेदारी 8% से बढ़कर 2017 में 15% हो गई. लेकिन आर्थिक बाधाएं अभी भी बनी हुई हैं. एक मेडिकल डिग्री की सालाना लागत लगभग 97,400 रुपये है, जबकि इंजीनियरिंग की पढ़ाई में करीब 23 लाख रुपये खर्च होते हैं. रिपोर्ट के अनुसार, ये खर्च गरीब परिवारों की वार्षिक आय से अधिक होते हैं, जिससे पेशेवर कोर्स तक पहुंच सीमित हो जाती है और उच्च आय वाले पेशों में असमानता बनी रहती है. जिन युवाओं को डिग्री मिलती है, उन्हें वेतन में स्पष्ट बढ़त मिलती है. शुरुआत में वे गैर-स्नातकों की तुलना में लगभग दोगुना कमाते हैं, और यह अंतर समय के साथ और बढ़ता है. हालांकि, युवा पुरुष स्नातकों के शुरुआती वेतन 2011 से स्थिर बने हुए हैं. वहीं, स्नातकों के बीच लैंगिक वेतन अंतर कम हुआ है और अब युवा महिला स्नातक अपने पुरुष समकक्षों के बराबर कमाई कर रही हैं.

रजिस्ट्रेशन आफ न्यूज पेपर्स (सेन्ट्रल रूल्स 1965 के अन्तर्गत) 'न्यूज रुटीन' मासिक पत्रिका के संबंध में स्वामित्व तथा अन्य विवरण विषयक जानकारी

घोषणा, फार्म-4 (नियम-8 देखिए)

1. प्रकाशन स्थल	-	ग्राम-पोस्ट-पवनी, तहसील-बिलाईगढ़, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा,(छग) 493338
2. प्रकाशन अवधि	-	मासिक
3. प्रकाशक का नाम	-	गुलाब दास दीवान
क्या मुद्रक भारतीय नागरिक हैं	-	भारतीय
या विदेशी हैं तो मूल देश	-	
पता	-	ग्राम-पोस्ट-पवनी, तहसील-बिलाईगढ़, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा,(छग) 493338
4. मुद्रक का नाम	-	गुलाब दास दीवान
क्या प्रकाशक भारतीय नागरिक हैं या विदेशी हैं तो मूल देश	-	भारतीय
पता	-	ग्राम-पोस्ट-पवनी, तहसील-बिलाईगढ़, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा,(छग) 493338
5. सम्पादक का नाम	-	गुलाब दास दीवान
क्या प्रकाशक भारतीय नागरिक हैं या विदेशी हैं तो मूल देश	-	भारतीय
पता	-	ग्राम-पोस्ट-पवनी, तहसील-बिलाईगढ़, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा, (छग) 493338
6. उन व्यक्ति के नाम व पते जो समाचारपत्र के स्वामी हों तथा समस्त पूंजी में एक प्रतिशत से अधिक सम्पूर्ण स्वामित्व के हिस्सेदार हों	-	गुलाब दास दीवान ग्राम-पोस्ट-पवनी, तहसील-बिलाईगढ़, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा, (छग) 493338

मैं गुलाबदास दीवान एतद् द्वारा घोषणा करता हूं कि शीर्षक न्यूज रुटीन जो बलौदाबाजार से प्रकाशित तथा मिशन मीडिया प्रा. लि. छत्तीसगढ़ भवन, प्रेस काम्पलेक्स, रजबंधा मैदान रायपुर से मुद्रित होने वाले समाचार पत्र का मुद्रक एवं प्रकाशक हूं तथा उक्त समाचार पत्र के संदर्भ में यहां दिये गये निम्न विवरण मेरी पूर्ण जानकारी एवं विश्वास के अनुरूप सत्य हैं।

दिनांक 1-3-2026 **गुलाब दास दीवान**

पदनाम- मुद्रक / प्रकाशक / स्वामी

अपने भीतर के हनुमान को जगाने का पर्व

हनुमान के जीवन में तीन महान तत्व दिखाई देते हैं-ज्ञान, भक्ति और कर्म। ज्ञान उन्हें दिशा देता है, भक्ति उन्हें प्रेरणा देती है और कर्म उन्हें महान बनाता है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में ज्ञान है पर कर्म नहीं, तो वह अधूरा है। यदि कर्म है पर भक्ति नहीं, तो उसमें संवेदना नहीं होगी। यदि भक्ति है पर ज्ञान नहीं, तो वह अंधविश्वास बन सकती है।

हनुमान जन्मोत्सव केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि मानव जीवन के चरित्र-निर्माण, आत्मबल, संयम, सेवा और समर्पण की प्रेरणा देने वाला महान दिवस है। यह दिन हमें मंदिरों में दीप जलाने से अधिक अपने भीतर के अंधकार को दूर करने का संदेश देता है। हनुमान केवल शक्ति के प्रतीक नहीं हैं, वे शक्ति के सदुपयोग, ज्ञान की विनम्रता, भक्ति की पराकाष्ठा और सेवा की परंपरा के प्रतीक हैं। इसलिए हनुमान जन्मोत्सव मनाने का वास्तविक अर्थ है- अपने भीतर के हनुमान को जगाना। हनुमान जी को मंगलकर्ता और विघ्नहर्ता कहा गया है। लेकिन वे विघ्न केवल बाहरी नहीं हटाते, वे मनुष्य के भीतर के विघ्न-अहंकार, भय, आलस्य, क्रोध, लोभ, मोह, इन सबका भी नाश करते हैं। आज का मनुष्य बाहरी समस्याओं से कम और आंतरिक कमजोरियों से अधिक परेशान है। इसलिए आज हनुमान की प्रासंगिकता पहले से कहीं अधिक है।

हनुमान शक्ति के प्रतीक हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने कभी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने अपनी शक्ति को सेवा में लगाया। आज का युग शक्ति प्रदर्शन का युग बन गया है-धन का प्रदर्शन, पद का प्रदर्शन, ज्ञान का प्रदर्शन, शक्ति का प्रदर्शन। लेकिन हनुमान हमें सिखाते हैं कि शक्ति और ज्ञान का प्रदर्शन नहीं, उसका संरक्षण और सदुपयोग ही महानता है। सर्वशक्तिमान होकर भी उन्होंने स्वयं को 'राम का दास' कहा। इससे बड़ी विनम्रता और क्या हो सकती है? हनुमान हमें यह भी सिखाते हैं कि शक्ति और ज्ञान का अहंकार नहीं होना चाहिए। ज्ञान यदि विनम्रता नहीं देता, तो वह अज्ञान है। शक्ति यदि सेवा में नहीं लगती, तो वह विनाश का कारण बनती है। इसलिए हनुमान शक्ति और ज्ञान के साथ-साथ विनम्रता और सेवा के भी प्रतीक हैं।

हनुमान को ज्ञानियों में अग्रगण्य कहा गया है- 'ज्ञानिनामग्रगण्यम'। वे केवल बलवान नहीं थे, वे महान विद्वान, व्याकरणाचार्य, तर्कशास्त्री, संगीतज्ञ और नीतिज्ञ भी थे। लेकिन इतनी विद्या होने पर भी उनमें अहंकार नहीं था। वे सरलता, सादगी और सेवा के प्रतीक बने रहे। आज शिक्षा बढ़ रही है, लेकिन विनम्रता घट रही है। डिग्रियाँ बढ़ रही हैं, लेकिन चरित्र घट रहा है। ऐसे समय में हनुमान का चरित्र हमें ज्ञान के साथ विनम्रता का संतुलन सिखाता है। हनुमानजी को हिन्दू देवताओं में सबसे शक्तिशाली माना गया है, वे रामायण जैसे महाग्रंथ के सह पात्र थे। वे भगवान शिव के ग्यारवें रूद्र अवतार थे जो श्रीराम की सेवा करने और उनका साथ देने त्रेता युग में अवतरित हुए थे। उनको बजरंग बलि, मारुतिनंदन, पवनपुत्र, केशरीनंदन आदि अनेकों नामों से पुकारा जाता है। उनका एक नाम वायुपुत्र भी है, उन्हें वातात्मज भी कहा गया है अर्थात् वायु से उत्पन्न होने वाला। इन्हें सात चिरंजीवियो में से एक माना जाता है। वे सभी कलाओं में सिद्धहस्त एवं माहिर थे। वीरो में वीर, बुद्धिजीवियों में सबसे विद्वान। इन्होंने अपने पराक्रम और विद्या से अनेकों कार्य चुटकीभर समय में पूर्ण कर दिए है। वे शौर्य, साहस और नेतृत्व के भी प्रतीक हैं। समर्पण एवं भक्ति उनका सर्वाधिक लोकप्रिय गुण है। रामभक्त हनुमान बल, बुद्धि और विद्या के सागर तो थे ही, अष्ट सिद्धि और नौ निधियों

के दाता और ज्योतिष के भी प्रकांड विद्वान थे।

हनुमान के जीवन में तीन महान तत्व दिखाई देते हैं- ज्ञान, भक्ति और कर्म। ज्ञान उन्हें दिशा देता है, भक्ति उन्हें प्रेरणा देती है और कर्म उन्हें महान बनाता है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में ज्ञान है पर कर्म नहीं, तो वह अधूरा है। यदि कर्म है पर भक्ति नहीं, तो उसमें संवेदना नहीं होगी। यदि भक्ति है पर ज्ञान नहीं, तो वह अंधविश्वास बन सकती है। इन तीनों का समन्वय यदि किसी चरित्र में दिखाई देता है, तो वह हनुमान का चरित्र है। हनुमान का जीवन संयम का जीवन था। वे बलशाली थे, पर ब्रह्मचारी थे। वे विद्वान थे, पर विनम्र थे। वे वीर थे, पर शांत थे। वे शक्तिशाली थे, पर सेवक थे। यह संतुलन ही उन्हें महान बनाता है। आज मनुष्य के पास साधन हैं, पर संयम नहीं। ज्ञान है, पर दिशा नहीं। शक्ति है, पर सेवा नहीं। इसलिए समाज में अशांति बढ़ रही है। हनुमान का जीवन हमें संयम और संतुलन का संदेश देता है।

हनुमान के बाल स्वरूप की कथा भी अत्यंत प्रेरणादायक है। बालक हनुमान ने सूर्य को फल समझकर पकड़ने का प्रयास किया। यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि एक महान संदेश है। यह बालकों की असीम जिज्ञासा, उत्साह और ऊर्जा का प्रतीक है। यह कथा समाज को संदेश देती है कि बच्चों की जिज्ञासा को दबाया नहीं जाना चाहिए, उसे सही दिशा देनी चाहिए। यदि बालकों को सही मार्गदर्शन मिले, तो उनमें से हर बालक हनुमान बन सकता है- ऊर्जावान, जिज्ञासु, साहसी और रचनात्मक। आज के माता-पिता और समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वे बच्चों में हनुमान जैसे गुण विकसित करें-साहस, जिज्ञासा, अनुशासन, सेवा, विनम्रता और भक्ति। यदि बचपन में ही यह संस्कार मिल जाएं, तो समाज का भविष्य उज्ज्वल हो सकता है। हनुमान भक्ति का वास्तविक अर्थ भी समझना जरूरी है। हनुमान भक्ति केवल चालीसा पढ़ना नहीं है, बल्कि हनुमान के गुणों को जीवन में उतारना है।

हनुमान भक्ति का अर्थ है- अहंकार छोड़ना, सेवा करना, सत्य का साथ देना, संयम रखना, कर्तव्य निभाना और अपने जीवन को किसी महान उद्देश्य से जोड़ना। जब तक भक्ति केवल मंदिर तक सीमित रहेगी, तब तक भगवान अलग रहेंगे और भक्त अलग रहेगा। जब भक्ति जीवन बन जाती है, तब भगवान और भक्त अलग नहीं रहते। हनुमान की भक्ति प्रदर्शन नहीं, आत्मपरिवर्तन की प्रक्रिया है। यह भक्ति व्यक्ति को भीतर से बदल देती है-अहंकार की जगह विनम्रता, क्रोध की जगह क्षमा, भय की जगह साहस और निराशा की जगह आशा भर देती है। आज समाज में सबसे बड़ी समस्या शक्ति की नहीं, चरित्र की है; ज्ञान की नहीं, दिशा की है; साधनों की नहीं, संयम की है। इसलिए आज समाज को हनुमान की जरूरत है-मंदिरों में नहीं, जीवन में; मूर्तियों में नहीं, व्यक्तित्व में। हर व्यक्ति के भीतर एक हनुमान सोया हुआ है- किसी में साहस का हनुमान, किसी में सेवा का हनुमान, किसी में ज्ञान का हनुमान, किसी में भक्ति का हनुमान। जरूरत केवल उसे जगाने की है।

अपने भीतर के हनुमान को जगाने का अर्थ है- अपने भीतर के भय को हराना, अपने भीतर के अहंकार को मिटाना, अपने भीतर की शक्ति को सेवा में लगाना, अपने ज्ञान को समाज के काम में लगाना, अपने जीवन को किसी महान उद्देश्य से जोड़ना। यदि हनुमान जयंती पर हम केवल पूजा करें और जीवन न बदलें, तो यह पर्व अधूरा है। यदि हम अपने जीवन में साहस, सेवा, संयम, विनम्रता और भक्ति का एक भी गुण उतार लें, तो हनुमान जयंती सार्थक हो जाएगी। आज आवश्यकता मंदिरों में हनुमान खोजने की नहीं, अपने भीतर हनुमान जगाने की है। जब व्यक्ति के भीतर हनुमान जागेगा, तब उसका भय समाप्त होगा। जब समाज के भीतर हनुमान जागेगा, तब अन्याय समाप्त होगा। जब राष्ट्र के भीतर हनुमान जागेगा, तब कमजोरी समाप्त होगी।

हनुमान जन्मोत्सव हमें यही संदेश देती है कि महानता शक्ति में नहीं, शक्ति के सदुपयोग में है; ज्ञान में नहीं, ज्ञान की विनम्रता में है; भक्ति में नहीं, भक्ति के समर्पण में है।

बादलों के बीच बसा आइजोल

भारत के पूर्वोत्तर में बसा छोटा सा राज्य मिजोरम अपनी नैसर्गिक प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। मिजोरम की राजधानी आइजोल तो जैसे बादलों की गोद में बसी एक शांत दुनिया है, जहां हर मोड़ पर प्रकृति मुस्कुराती हुई नजर आती है।

मिजोरम की यात्रा प्रकृति, संस्कृति और सादगी से जुड़ने का अवसर है। आइजोल शहर में घूमने का अनुभव भी अनोखा है। शहर घूमते समय आप किसी भी वाहन का हॉर्न नहीं सुनेंगे।

सड़क पर वाहन एकदम अनुशासित तरीके से चलते मिलेंगे। हर कोई आपसे मुस्कुरा कर बात करेगा। दुकान, होटल, रेहड़ी सब जगह महिलाएं काम करती दिखेंगी। सोलोमन टैंपल की शांति, स्काईवॉक का रोमांच और कहानियां सुनाती रैक की पहाड़ियां दिल को छू लेती हैं। भीड़-भाड़ से दूर, सुकून भरे किसी स्थान पर घूमने की तलाश में हैं तो मिजोरम की यह खूबसूरत राजधानी आपका इंतजार कर रही है।

आइजोल -साइलेंट सिटी की सादगी

आइजोल को साइलेंट सिटी कहा जाता है। यहां का अनुशासन, साफ-सफाई और लोगों की सादगी इसे देश के अन्य शहरों से अलग बनाती है। सड़कें व्यवस्थित हैं। लोगों को विनम्र स्वभाव बहुत अच्छा अहसास करवाता है। यहां आपको हर घर के बाहर गमलों में फूल खिले दिखेंगे। यह शहर घूमने तक समिति नहीं रहता, बल्कि यहां की खूबसूरती और सुकून दिल में बस जाते हैं।

आइजोल जाने के लिए हवाई जहाज से लेंगपुई तक जाया जा सकता है। यहां से आइजोल शहर की दूरी 32 किलोमीटर है।

हर मोड़ पर मुस्कुराती है प्रकृति, पहाड़ सुनाते हैं कहानियां

लेंगपुई एयरपोर्ट से आपको राजधानी के लिए आसानी से टैक्सी मिल जाती है। दूसरा विकल्प ट्रेन है। सायरांग रेलवे स्टेशन अब दिल्ली से जुड़ गया है। दिल्ली से सीधे राजधानी अब सायरांग तक जाती है। इसके अलावा कोलकाता और असम से भी ट्रेन के माध्यम से सायरांग पहुंचा जा सकता है। सायरांग से आइजोल केवल 20 किलोमीटर है।

रैक-प्रकृति के रंगों में रंग जाते हैं पहाड़

रैक पहाड़ियां मिजोरम के सबसे लोकप्रिय और खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक है। यह स्थान राजधानी आइजोल से करीब 30 किलोमीटर दूर है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1,400 से 1,500 मीटर है। यहां का दृश्य इतना मनमोहक है कि इसकी चोटी से आप चारों ओर दूर-दूर तक सभी पहाड़ों को 360 डिग्री घूम कर देख सकते हैं।

रैक की पहाड़ियां घने जंगल और बादलों से ढकी रहती हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय प्रकृति इन पहाड़ों को अपने रंग में रंग देती है। यहां पहुंचते ही मन प्रकृति के साथ एकाकार हो जाता है।

यह जगह ट्रैकिंग प्रेमियों के लिए भी कम खास नहीं है। यहां की पारंपरिक मिजो झोपड़ियां और लोक संस्कृति इस यात्रा को और भी खूबसूरत बना देती हैं। आइजोल से टैक्सी लेकर यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है।

आइजोल स्काइवॉक पर जाना बहुत रोमांचक है। जब भी आइजोल जाएं तो इस रोमांच का अनुभव जरूर करें। कांच और स्टील से बना यह स्काईवॉक पहाड़ियों के ऊपर बना है। यहां खड़े होकर नीचे देखने का अनुभव अलग अहसास करवाता है। यहां से पहाड़ों पर बसे आइजोल शहर की खूबसूरती को निहारा जा सकता है। रात के समय यहां से शहर को देखना अद्भुत है। दूर तक फैले घर और बादलों का खेल दिल में बस जाता है। स्काईवॉक आइजोल शहर के साथ लगती पहाड़ी पर है। यहां टैक्सी लेकर आसानी से पहुंचा जा सकता है।

सोलोमन टेंपल- आस्था और स्थापत्य का संगम

आइजोल की घुमावदार सड़कों से गुजरते हुए जब सोलोमन टेंपल (चर्च) की पहली झलक मिलती है, तो मन ठहर सा जाता है। इसकी अनोखी वास्तुकला और सफेद रंग में नहाया यह विशाल परिसर आपको अपनी ओर खींच लेता है। चारों ओर शांति और अनुशासन एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं।

न कोई शोर, न कोई भाग-दौड़, बस एक गहरा सुकून

यह जगह केवल देखने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने के लिए है। यहां आप खुद से जुड़ पाते हैं। इस चर्च का निर्माण एलबी सैलो ने करवाया था। बताते हैं कि उन्हें एक रात दिव्य स्वप्न आया, जिसके बाद इसका निर्माण शुरू किया गया। वर्ष 2017 में इसे लोगों के लिए खोला गया। यहां एक समय में दो हजार लोग प्रार्थना कर सकते हैं। यह आइजोल में ही स्थित है।

आत्मनिर्भरता की मिसाल बनीं ग्रामीण महिलाएं

गृह उद्योग और हस्तशिल्प से संवर रहा भविष्य

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के प्रभावी क्रियान्वयन से रायगढ़ जिले की ग्रामीण महिलाएं आज आत्मनिर्भरता की दिशा में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रही हैं। यह योजना महिलाओं को न केवल आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास, कौशल और सामाजिक पहचान भी प्रदान कर रही है।

रायगढ़ जिले के ग्राम बड़ेभंडार की निवासी श्रीमती मथुरा कुर्रे इसकी उदाहरण हैं। उन्होंने बताया कि बिहान योजना से जुड़ने के पश्चात उन्हें रिवॉल्विंग फंड एवं कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड के तहत आर्थिक सहयोग प्राप्त हुआ। इस सहयोग से उन्होंने घर पर ही अचार, पापड़, बड़ी एवं मसाला निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। आज वे अपने उत्पादों का बाजार में विक्रय कर नियमित आय अर्जित कर रही हैं, जिससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और वे आत्मनिर्भर बन सकी हैं।

इसी क्रम में ग्राम रूमकेरा, तहसील घरघोड़ा की श्रीमती जमुना सिदार की कहानी भी प्रेरणादायक है। पूर्व में वे एक गृहिणी थीं, किन्तु बिहान योजना से जुड़ने के बाद उन्होंने बांस शिल्प का प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण उपरांत उन्होंने टोकरी, सूपा एवं अन्य हस्तशिल्प उत्पादों का निर्माण प्रारंभ किया। उन्हें विभिन्न मेलों, विशेषकर 'सरस मेला' में अपने उत्पादों के प्रदर्शन और विक्रय का अवसर प्राप्त हुआ, जिससे वे अच्छी आय अर्जित कर रही हैं। इससे उनके जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन आया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन महिलाओं को केवल आर्थिक सहायता ही नहीं, बल्कि कौशल विकास, उद्यमिता और आत्मगौरव का अवसर भी प्रदान कर रहा है। जिले में अनेक महिलाएं इस योजना से जुड़कर स्वरोजगार के माध्यम से अपने जीवन को नई दिशा दे रही हैं।

शासन के मंशानुरूप जिला प्रशासन रायगढ़ द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। विभिन्न योजनाओं से जोड़कर महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जा रहा है, जिससे वे न केवल अपने परिवार की आय में वृद्धि कर रही हैं, बल्कि समाज में एक सशक्त भूमिका भी निभा रही हैं।

बिहान योजना आज जिले में महिला सशक्तिकरण का सशक्त माध्यम बनी है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हुए आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।

नक्सलवाद का अंधेरा छोड़ शर्मिला ने थामी स्वावलंबन की सुई

बस्तर संभाग के नक्सल मुक्त घोषित होने के बाद अब हिंसा का रास्ता छोड़ मुख्यधारा में लौटने वाले युवाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन दिखने लगा है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल बीजापुर की शर्मिला पोयामी बनकर उभरी हैं, जिन्होंने कभी हाथों में बंदूक थामी थी, लेकिन आज वे लाइवलीहुड कॉलेज में सुई-धागे से अपने और अपने परिवार के भविष्य के सपने बुन रही हैं।

बीजापुर जिले के भैरमगढ़ ब्लॉक की रहने वाली 19 वर्षीय शर्मिला कभी भैरमगढ़ एरिया कमेटी की सक्रिय सदस्य थीं। गुरिल्ला युद्ध और हथियारों का प्रशिक्षण लेने वाली शर्मिला को जल्द ही अहसास हो गया कि प्रगति का मार्ग बंदूक से नहीं, बल्कि शांति और शिक्षा से निकलता है। इसी संकल्प के साथ उन्होंने 07 फरवरी 2026 को आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का निर्णय लिया।

राज्य शासन की पुनर्वास नीति के तहत शर्मिला को दंतेवाड़ा के लाइवलीहुड कॉलेज में प्रवेश दिलाया गया। बीते 45 दिनों से वे यहाँ सिलाई का गहन प्रशिक्षण ले रही हैं। अब वे आधुनिक परिधान जैसे सूट और ब्लाउज सिलने की बारीकियां सीख रही हैं। प्रशिक्षण के बाद उनका लक्ष्य अपने गाँव लौटकर सिलाई केंद्र खोलना और अपनी 4 एकड़ पुश्तैनी जमीन पर आधुनिक खेती (टमाटर, मूली व भाजियाँ) कर परिवार को आर्थिक संबल प्रदान करना है।

शर्मिला ने बताया कि मुख्यधारा में लौटने के बाद उन्हें पहली बार शासन की ओर से इतनी बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं, पौष्टिक आहाररू कॉलेज में नियमित रूप से अंडा, मछली, चिकन और हरी सब्जियां दी जा रही हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य में बड़ा सुधार हुआ है। सक्रिय सहभागितारू बढ़ते आत्मविश्वास का ही परिणाम है कि उन्होंने हाल ही में जगदलपुर में आयोजित मैराथन दौड़ में भी हिस्सा लिया।

महिला मज़दूर वंचित व शोषित वर्ग के पक्षधर,
संविधान निर्माता, भारत रत्न

बाबा साहेब
डॉ.भीमराव अंबेडकर जी

की जयंती पर आप सभी को

हार्दिक शुभकामनाएं

न्यूज रूटीन परिवार